Concern over suicides by farmers in Vidarbha region of Maharashtra

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कपास उत्पादक और अन्य किसानों द्वारा कर्ज के बोझ से दबे रहने का कारण की जा रही आत्महत्याओं की तरफ मैं प्राय: हर सत्र में आपके माध्यम से विशेष उल्लेख द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। सरकार ने विदर्भ के लिए अनेक पैकेजों की घोषणा भी की है, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं रुक नहीं रहीं हैं। अभी पिछले महीने जनवरी, 2007 में 62 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। फरवरी, 2007 में भी आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। ऐसा प्रतीत होता है, सरकार द्वारा दी जा रही सहायता किसानों तक नहीं पहुंच रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 में 1050 से भी अधिक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। यह अत्यन्त भयावह और चिन्ता की स्थिति है। सरकार द्वारा जो भी सहायता दी गई है, उसका कपास उत्पादक किसानों को बहुत कम लाभ मिल पाया है।

मेरा अनुरोध है कि विदर्भ के किसानों को जो सहायता दी जा रही है, वह उनको मिल रही है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यह पता लग सके कि जो सहायता किसानों को दी गई है, क्या वह उनको मिल गई है?

मेरा सरकार से यह भी कहना है कि कपास उत्पादक विदर्भ के किसानों की स्थिति पर गंभीरता से विचार कर उन कारणों को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए, जिनके कारण किसान आत्महत्याएं करने के लिए बाध्य हो रहे हैं।

Motion of thanks on President's Address

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, मैं डा॰ कर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने तमाम महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है। चूंकि हमारे विद्वान वक्ताओं ने तमाम चीजों पर पहले ही अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ बिन्दुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आज देश ने 60 साल में पहली बार 9 प्रतिशत से ऊपर की विकास दर प्राप्त की है हमें इस सरकार के नेतृत्व में यह विकास दर प्राप्त हुई है। इसका सभी दलों को समर्थन करना चाहिए, बजाए इसके कि इसको आलोचनाओं और प्रत्यालोचनाओं के दायरे में लाया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज पूरा विश्व हमें एक इमर्जिंग इकनोमी की तरह देख रहा है। भारत की ऐसी आर्थिक उन्नति हो रही है कि पूरा विश्व हमारी तरफ टकटकी लगाए हुए है और हम आलोचना के दायरे में फंसे हुए हैं। इससे यह होता है कि जब ये बातें बाहर

जाती हैं तो विदेशों में भी लोग यह समझते हैं कि क्या भारत के अंदर कहीं कोई बात खोखली तो नहीं है। इसलिए हमें आलोचनाओं और प्रत्यालोचनाओं से बचना चाहिए। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को महंगाई से लिंक किया जाता है। प्राइस राइस एक ऐसा मुद्दा है, इससे हम सब सहमत हैं कि प्राइस राइस को रोकना चाहिए और इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, चाहे इसके लिए जो भी कदम उठाए जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लगातार महंगाई रोकने की बात करती रहती हैं, लेकिन यह मानना चाहिए कि यह एक टेम्परेरी चीज है। यह महंगाई कुछ वक्त के लिए है और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आज यह बात कह सकता हूं कि एक डेढ़ महीने पहले जो स्थिति थी, उसमें अब सुधार हुआ है। चीनी 6 रुपए किलो नीचे आई हैं गेहूं और चावल के दामों में भी कमी आई है। स्टील के दामों में भी कमी आई है और वित्त मंत्री जी का सीमेंट के दाम कम करने के लिए लगातार प्रैशर व दबाव चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि दामों में कमी लाने के लिए प्रयास नहीं हो रहा है। मैंने अभी ये पांच-छः आवश्यक वस्तुएं बताई हैं, जिनके दामों में कमी आई है और कोई भी आदमी इनको बाजार में जाकर चैक कर सकता है। मैं यहां पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ना चाहूंगा कि आज देश में जो हालत है, वह यह है कि अभी हम पचास हजार करोड़ के एग्रीक्लचर प्रोडक्ट्स आयात कर रहे हैं। हमारा 2020 तक का जो अनुमान है, उसमें हमें अपनी भारतीय जनता के लिए कम से कम पांच लाख करोड़ के एग्रीक्लचर प्रोडक्ट्स आयात करने पड़ेंगे। यह स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि हमारे देश में अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है और एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है तथा लैंड होल्डिंग्स कम होती चली जा रही हैं। इसकी वजह से जनसंख्या और भी बढ़ रही है, तो खाद्य पदार्थों की कमी स्वाभाविक है। हमें इससे आगे और बड़ा चेलेंज मिलने जा रहा है। दूसरे प्राइवेट सैक्टर्स के लोग लगातार फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, इसलिए इस बार व्हीट का प्रोक्योरमेंट कम हुआ है। यह एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आई है। यह सबसे बड़ी चीज है कि अर्बनाइजेशन करते समय यह ध्यान रखें कि हम एग्रिक्लचर लैंड, फर्टाइल लैंड को कम से कम इस्तेमाल में लाएं। मुझे याद है, जब राजीब गांधी जी थे, तो उन्होंने एक वेस्टलैंड मिनिस्ट्री बनाई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश की 27 परसेंट जमीन ऊसर जमीन है, वेस्टलैंड जमीन हैं मेरा यह मानना है कि जितने भी नए SEZ दिए जाएं, जितना भी नया इंडस्ट्रियालाइजेशन हो, जितना भी नया अर्बनाइजेशन हो, हाऊसिंग कॉलोनी हो, हम क्यों नहीं नए टाऊनशिप वेस्टलैंड में बनाते हैं। जो ऊसर जमीन है, उसमें चमन करो, जिस तरह सीरिया ने किया है। इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए सरकार को वेस्टलैंड वाले proposal को consider करना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण में जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। कल इस विषय पर हमारे सांसद डा॰ पी॰सी॰ अलेक्जेन्डर साहब ने भी अपनी बात रखी थी। मैं इनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, इसलिए मैं यह महत्वपूर्ण और अहम बात सदन के सामने रख रहा हूं। आज जिस तरह से ज्यूडिशियरी में करप्शन की बात हो रही है, यह

जगह-जगह चर्चा का विषय बन चुकी है। दो-दो हाई कोर्ट्स के जज़ेस की फाइलें इसी आधार पर प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया ने वापस की हैं। तमाम जगह जज़ेस की शिकायतें हो रही हैं। करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। चाहे गुजरात का मसला हो, चाहे अन्य राज्यों का मसला हो, लेकिन हम इन्हें होली काऊ बनाकर बिठाए हुए हैं। इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इन्होंने क्या किया कि धीरे-धीरे सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। अब यह जो ज्यूडिशियल कौंसिल बनाने की बात हो रही है, इसमें भी सिर्फ जज़ेस को छोड़ दिया गया है। सिर्फ जज़ेस तय करेंगे कि कौन ठीक है, कौन बुरा है। यह कैसे हो सकता है? इसमें एक्ज्यूकेटिव के रिप्रेजेंटेटिव्ज क्यों नहीं हैं? इसमें समाज के दूसरे वर्गों के प्रतिनिधि क्यों नहीं हैं? सिर्फ जजों के बारे में जज ही फैसला करेंगे। जब समाज के हर वर्ग के बारे में आप फैसला करते हैं तो आपके बारे में भी दूसरों को फैसला करने का अधिकार होना चाहिए। स्पीकर और चेयरमैन तक से अधिकार लिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट तक से अधिकार जा रहा है। अगर जनता हमें चुनती है तो इसलिए चुनती है कि हम पूरे देश पर राज करें। हमें मतदाताओं और जनता ने प्रतिनिधित्व दिया है। यह इसलिए नहीं दिया है कि कुछ वर्ग छोड़ दिए जाएं, सिर्फ इसलिए कि मीडिया एक प्रेशर पैदा करता है। मीडिया के प्रेशर में आकर राजनीतिज्ञ अपने सारे अधिकार, जो प्रजातंत्र में दिए गए हैं, उन्हें छोड़ते चले जा रहे हैं। यह सिर्फ इस डर से है कि छवि बिगड़ जाएगी। मेरा सरकार से बहुत स्पष्ट शब्दों से अनुरोध है कि ज्यूडिशियल कौंसिल में निश्चित रूप से दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। सिर्फ जज जज के बारे में तय न करे। न पोलिटिशियन को पोलिटिशियन के बारे में तय करने का अधिकार देना चाहिए, न ब्यूरोक्रेट्स को ब्यूरोक्रेट्स के बारे में तय करने का अधिकार देना चाहिए। ऐसे समाज और देश नहीं चलता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है। खासतौर से जब लगातार जज़ेस के बारे में शिकायतें आ रही हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री बालाकृष्णन साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खुद इस बात को हाईलाइट किया है और कहा है कि मैं ज्यूडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करूंगा और जज़ेस की जो तमाम शिकायतें हैं, उनसे सख्ती से निपटूंगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस बात पर विचार करें। ऑल इंडिया ज्यूडिशियल कौंसिल में एग्ज्यूकेटिव के लोग आएं।

एक और इम्पोर्टेन्ट बात है आप पहले के जज़ेस उठा लीजिए। जब सरकार, एग्ज्यूकेटिव या सब जगह के चीफ मिनिस्टर्स, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सभी मिलकर ज्यूडिशियरी के साथ बनाते थे, वह लाट बहुत अच्छी आई थी। पिछले पचास-साठ साल के उन जज़ेस की अभी तक तारीफ है। अभी सिर्फ ज्यूडिशियरी के हाथ में सारे जज़ेस दे दिए गए हैं। इसके बाद क्या तस्वीर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। किस-किस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि जो पुराना प्रोसेस था, प्रोसिजर था, उसी को अडोप्ट किया जाना चाहिए।

मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभषण में एक बात इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी है। आज नक्सलवाद निश्चित रुप से एक बड़ी चिंता हो रही है। हर तरफ, कई राज्य बुरी तरह से इसकी चपेट में हैं। मुझे लगता है कि इसे रोकने के लिए राज्यों और केंद्र का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इसके साथ-साथ इनसे कौन लड़ रहा है? पैरा मिलिट्री फोर्स लड़ रही है। पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ के लोगों की हालत बहुत खराब है। अगर आप उनके जवानों को देखें तो उनकी पोस्टिंग इतनी कठिन होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसके बदले में जो वेतन और सुविधाएं होती हैं, वे बहुत कम होती हैं। जो थाने में पुलिस तैनात है, उनको उनसे कम्पेयर करते हैं तो पाते हैं कि थाने की पुलिस बहुत मजे में है। पैरा मिलिट्री फोर्स, जो देश की सारी समस्याओं से लड़ रही है, उसका बुरा हाल है। पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ के जो जवान हैं, उनके इमोल्यूमेंट्स, उनकी सैलरी, उनके पर्क्स पर सरकार को विचार करना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है।

रूरल एम्प्लोएमेंट गारंटी स्कीम एक ऐसी योजना है जिससे गांव में रोजगार बढ़ाने का निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। अभी तक इस पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया था, अभी 2000 कोड़ रुपए खर्च होने बाकी हैं। 64 करोड़ मेंडेट अलॉट किए जा चुके हैं। इसकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं क्योंकि पहला प्रयोग है, पहला अनुभव है। चूंकि राज्य सरकारों के जरिए लागू हो रहा है, इसलिए राज्य सरकारों की इस मामले में मॉनिटरिंग के जरिए कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि इसका सही सदुपयोग हो। गांव में जो जरुरतमंद लोग हैं यह उन तक पहुंचे। जिन-जिन राज्यों में इस स्कीम का दुरुपयोग हो रहा है, उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। उन राज्यों को पैसा देने से पहले कुछ सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके बारे में कोई मोनिटरिंग एजेंसी अवश्य बिठानी चाहिए।

यहां पर प्रफुल्ल पटेल जी नहीं हैं। मैं उनके लिए यह कहना चाह रहा था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आया है कि जो पीक ऑवर्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सबके लिए डबल चार्जेज लगाने की बात आई है। मैं भी यह मानता हूं कि यह कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। मैं इसकी बजाय उलटा सुझाव दे रहा हूं। जो नॉन पीक ऑवर्स हैं, आप उसमें इंसेटिव्स दे दीजिए। इसमें कम कर दीजिए। चाहे लैंडिंग चार्जेस हो, चाहे टैरिफ हो, चाहे पैसेंजर में कम कर दो। इससे लोग अपने आप उसमें बढ़ेंगे, बजाय इसके कि आप पीक ऑवर्स में बढ़ाइए। अपने आप क्लॉगिंग बंद हो जाए।

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र): पीक ऑवर में ठीक नहीं है।

श्री राजीव शुक्ल: वही तो कह रहे हैं कि समस्या आपकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार नहीं हुआ, कंज्यूमर क्यों सफर करे। इसलिए इस पीक ऑवर्स वाले प्वाइंट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इसे रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री सीताराम येचुरी जी ने foreign policy के बारे में जो बात कही है, IPSA और BRICKS वाली, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। हमें निश्चित रूप

से इस तरह का ग्लोबल फोरम डेवलप करना चाहिए। जिन देशों की economy merge कर रही है या merge कर चुकी है, यदि उनका एक ब्लॉक बने, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। इनके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं और यह देश के लिए अच्छा रहेगा। इसमें किसी से टकराव की बात नहीं है, किसी के सामने खड़ा नहीं किया जा रहा है, यह किसी से प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का ब्लॉक हमारी economy की मदद करने के लिए उभरता है और जो देश बढ़ रहे हैं, आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, उनका एक ब्लॉक बनता है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है।

उपसभापति जी, आदरणीय जनेश्वर जी इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे, हम सब उनका सम्मान करते हैं, वे बुजुर्ग हैं और किसी जमाने में उन्हें ''लोहिया'' के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, हालांकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वे मुद्दे नहीं हैं, उनमें से एक मुद्दा उत्तर प्रदेश का भी उठाया है और उन्होंने कहा है कि लगातार प्रधान मंत्री की सरकार, वहां के मुख्य मंत्री को सता रही है। मैं खुद मानता हूं कि लोकतंत्र में किसी को सताने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और न सताया जाना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी के सताने का प्रश्न कहां से उठता है? अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का आदेश देती है, तो उसमें प्रधान मंत्री कहां से आड़े आते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसी किस्म का आदेश श्री लालू यादव के खिलाफ आए, तो उसका स्वागत है, मायावती के खिलाफ आए, तो उसका स्वागत है, तो यह pick and choose नहीं हो सकता कि एक के खिलाफ आए, तो स्वागत है, बाकी के खिलाफ आए, तो आलोचना मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है...(व्यवधान)

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): आप भी वही कह रहे हैं। जो आपको suit करता है, वह लाजिम है, जो आपको suit नहीं करता, वह लाजिम नहीं है, आप भी वही कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: वे yield नहीं कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती जया बच्चन: राजीव जी, आप जनेश्वर जी के लिए जो कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं ...(व्यवधान) हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से बात करिए .... (व्यवधान)

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): मैडम, ये जो कह रहे हैं, वही कर भी रहे हैं .... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए .... (व्यवधान) आपकी तरफ इशारा नहीं था, आप क्यों उठ रहे हैं ...(व्यवधान) बोलिए, बोलिए .... (व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल: जया जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम यह कह रहे हैं कि इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मामले में इसी एजेंसी को कहा जाए कि यह Congress Bureau of Investigation है और लालू या मायावती जी के मामले में कहा जाए कि यह Congress Bureau of Investigation नहीं है, यह बड़ी independent agency है। आपकी सरकार ही कई बार मांग करती है कि CBI को यह मामला सौंप दिया जाए। तो एक मामले में CBI की साख है, दूसरे मामले में नहीं है, या तो तय हो जाए कि CBI की कोई साख है या नहीं .....(व्यवधान)

श्री उपसभापति: वह छोड़िए, यहां इस पर बहस नहीं हो रही है ....(व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल: या तो तय हो जाए कि कोई साख नहीं है या साख है, सब लोग मिलकर तय कर लें, यह pick and choose नहीं हो सकता कि एक मामले में साख है, दूसरे मामले में साख नहीं है, यह मेरा कहना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shuklaji, please, address the Chair.

श्री राजीव शुक्ल: गेम के रूल्स एक होने चाहिए, खेल के नियम ....(व्यवधान)

श्री उपसभापति: आप लोग बैठकर बात मत कीजिए ....(व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल: मेरा सिर्फ यह कहना है कि खेल के दो नियम नहीं हो सकते हैं। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर है–नौएडा प्लॉट आवंटन पर CBI enquiry का, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट रोक देता है, तो सुप्रीम कोर्ट सही है और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई दूसरा ऑर्डर करता है, तो फिर judiciary बेकार है, judiciary खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, मेरे ख्याल से यह ....(व्यवधान)

श्रीमती जया बच्चन: सर, ये बहुत गलत बोल रहे हैं ....(व्यवधान) किसी ने यह कहा, How can he say this?... (*Interruptions*). But this is going on record I disagree. He cannot say this. We have never said anything against judiciary.

श्री उपसभापति: जया जी, आप जो बोलती हैं, वह आपका अधिकार है, वे जो बोलते हैं, वह उनका अधिकार है, अभी उदय प्रताप सिंह जी बोलेंगे, तब बता देंगे। आपकी पार्टी की ओर से वे बोल रहे हैं, उस वक्त आप बता दीजिए .... (व्यवधान)

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: बिल्कुल सही कह रहे हैं, but, he cannot accuse us that we have said that judiciary is wrong. यह बार-बार कहा गया है ....(व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rajeev Shukla, please, address the Chair.

श्रीमती जया बच्चन: आप गलत बोल रहे हैं ...(व्यवधान) क्या कर रहे हैं आप ...(व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल: मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं ...(व्यवधान)... I am not yielding.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Don't put words in our mouth.

श्री उपसभापति: शुक्ल जी, आप केवल चेयर को address कीजिए, उनको मत address कीजिए ... (व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल: महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि ...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: He is putting words in our mouth. We have never ever said anything against judiciary.

श्री राजीव शुक्ल: उपसभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस प्रकार के प्रकरण नहीं आते हैं, लेकिन जनेश्वर जी ने इसका जिक्र किया और प्रधानमंत्री जी पर आक्षेप किया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। इसमें न सरकार का कोई हस्तक्षेप है, न कांग्रेस पार्टी का कोई हस्तक्षेप है, यह मैं कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट सब मामलों में सही है, सब मामलों में सही है, यह हम मानते हैं, CBI सब मामलों में सही है, तो सही है, अगर सब मामलों में गलत है, तो गलत है–यह मेरा कहना है, मैं किसी pecific case की बात नहीं कर रहा हूं।

उपसभापति जी, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ....

श्री वी॰ नारायणसामी (पांडिचेरी): यू॰पी॰ के बारे में थी ...(व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल: नहीं, यू॰पी॰ के बारे में नहीं थी।

श्री उपसभापति: नारायणसामी जी, आप क्यों provoke कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल: जया जी की आपत्तियां बहुत आ रही हैं ... मैंने इन चार-पांच बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं, मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से सरकार इनकी ओर ध्यान देगी, खास तौर से judicial reforms, economic growth और foreign policy का जो issue है, इनकी ओर सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी, यही मेरा कहना है, धन्यवाद।

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि आपने धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। एक तो इस प्रस्ताव से महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम जुड़ा हुआ है और दूसरा यह आदरणीय डा॰ कर्ण सिंह जी के द्वारा प्रस्तावित है, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। इसलिए मैं यह कहूं कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर

रहा हूं, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैंने इसका विरोध नहीं किया, तो यह माना जाएगा कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं और इस सरकार से हमने समर्थन वापस ले लिया है। इसलिए मैं बड़ी दुविधा और संकोच में हूं कि जो कुछ कहूं, वह कैसे कहूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं।... (व्यवधान)...

श्री वी॰ नारायणसामी: सरकार से समर्थन withdraw करके उसके बाद बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह: एक मिनट, आप ऐसा मत बोलिए। मैं अच्छी बातें बोलूंगा। मैं कभी कड़वी बातें नहीं करता, इसलिए मैं अच्छी बातें करूंगा।

आदरणीय उपसभापति जी, सभ्यता के इतिहास में एक बात सामने आती है कि समता का महत्व बढ़ता चला गया। मनुष्य और मनुष्य के बीच के, समाज के हर हिस्से में बराबरी होनी चाहिए। बस इसी का नाम सभ्यता है। इसलिए तीन संस्थाएं पैदा हुई–एक डेमोक्रेसी, एक सेकुलरिज्म और एक सोशलिज्म। यह जो सामाजिक बराबरी पर आधारित है, उसका नाम सोशलिज्म है; जो राजनैतिक बराबरी पर आधारित है, उसका नाम डेमोक्रेसी है और जो धार्मिक बराबरी के आधार पर है, उसका नाम सेकुलरिज्म है। लेकिन ये तीनों संस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं, एक-दूसरे पर आधारित हैं। एक के बगैर दूसरी जिन्दा नहीं रह सकती। जिस देश में सेकुलरिज्म नहीं होता है, उसके दो उदाहरण हैं, एक हमारे पूर्व में है और एक पश्चिम में है। दोनों में जो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है, वह इतना नीचा है कि वह न के बराबर है। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि यह बराबरी, मैं उसी बात पर आऊंगा, जहां से अभी बात शुरू हो रही थी, सबसे बड़ी चीज़ है बराबरी। हमारे संविधान में भी तीनों बातें कही गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बराबरी पर तो कायम रहें और दूसरी बराबरी को नकार दें। पाकिस्तान और नेपाल उदाहरण हैं। वहां सेकुलरिज्म नहीं है, तो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी कितना कम है। मैं बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहता हूं रूस एक बड़ा देश है और वह समाजवाद का बहुत बड़ा पोषक रहा। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि वहां पर समाजवाद के बिखराव का कारण केवल एक था, अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन एक कारण यह भी था कि वहां पर जो सरकारें थी, उनमें जो आयरन कर्टेन था, उसमें डेमोक्रेसी का स्तर बहुत कम था। इसलिए मैं यह साबित करना चाहता हूं कि समाजवाद बिना डेमोक्रेसी के नहीं रह सकता, डेमोक्रेसी बिना सेकुलरिज्म के नहीं रह सकती। ये सब एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित हैं।

इतना कहने के बाद मैं अब कहना चाहता हूं कि कल से बहस हो रही है, तो सरकार के जो समर्थक हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं। या तो वे विकास दर की चर्चा कर रहे हैं या वे सेंसेक्स की चर्चा कर रहे हैं या वे कह रहे हैं कि हमारी सेविंग्स इतनी हैं, हमारा निवेश इतना है और इसलिए देश बहुत तरक्की कर रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह डेमोक्रेसी क्या डेमोक्रेसी है, जिसके एक

बहुत छोटे से हिस्से को तो लाभ हो रहा हो, लेकिन कालाहांडी, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, जहां पर गरीबी है, उनको उसका लाभ न मिल रहा हो। तो सबसे पहले मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं डेमोक्रेसी का केवल यह अर्थ नहीं है। महोदय, गांधी जी ने कहा था कि असली भारत गांवों में रहता है और गांधी जी ने यह भी कहा था कि हम आजादी के लिए आज़ादी नहीं चाहते हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज़ादी चाहते हैं। महोदय, व्यवस्था परिवर्तन का उनका आशय यह था कि जिन लोगों को कभी अधिकार नहीं मिले, उन को अधिकार मिलने चाहिए, जो गरीब हैं उन को खाना मिलना चाहिए। मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या इस मामले में वह सफल हुई है? आप याद रखिएगा, एक तरफ पैसा आ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, विकास दर बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है और निवेश बढ़ रहा है तो गैर-बराबरी भी बढ़ रही है। महोदय, याद रखिएगा कि यह गैर-बराबरी बहुत खतरनाक चीज है।

आदरणीय उपसभापति जी, कल आपने कहा था कि कविता नहीं सुनायी। अब मैं इसी बात को कविता से कहना चाहता हूं:

आंकड़े तुम्हारे कुछ भी कहते हों लेकिन,

सत्य यही है कि जनता और गरीब हुई।

उत्पादन तो बढ़ा मगर तहखानों में,

लाखों लोगों को रोटी नहीं नसीब हुई।

महोदय, हम राजाओं की बुराई करते थे, लेकिन लोकशाही, नेताशाही में क्या ऐसे नेता नहीं हैं जो नवाबों को भी मात कर रहे हैं? तब मैं कहना चाहता हूं:

समता के घर में जाने कैसी वृद्धि हुई,

संख्या नकली राजाओं और नवाबों की,

संसद में चर्चा चलती रही बहारों की,

सूख गयी सड़कों पर पौध गुलाबों की।

महोदय, मैं कह रहा था कि यह गैर-बराबरी बहुत खतरनाक स्थिति है। उसका कारण आप चाहे मानें या न मानें, लेकिन जब झारखंड के हमारे एक साथी की क्रूर हत्या की चर्चा हो रही थी, तब गृह मंत्री जी ने प्रकारांतर से स्वीकार किया था कि इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी हैं। आर्थिक कारण मानें आर्थिक गैर-बराबरी भी रहा हो। मैं मानता हूं कि असंतोष हमेशा गैर-बराबरी से होता है, इसलिए यह गैर-बराबरी बहुत खतरनाक चीज है। यह आतंकवाद नक्सलवाद, अतिवाद - इनके पीछे कहीं-न-कहीं इसका भी हाथ है। इसलिए मैं सरकार को एक चेतावनी के रूप में कह

रहा हूं कि यह गरीब और अमीर की जो खाई है, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन इस से भी ज्यादा खतरनाक है सियासी गैर-बराबरी। महोदय, गांधी जी ने कहा था कि देश को आजादी प्राप्त हो गयी और जिस लक्ष्य के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, वह पूरा हो चुका है, इसलिए इसे disband कर दो। इसका मतलब यह है कि गांधी जी का इशारा था कि रीजनल प्रॉब्लम्स आएंगी, क्षेत्रवाद आएगा, अपने-अपने क्षेत्र के स्वार्थ पैदा होंगे और नई पार्टियां आएंगी। इसलिए यह उन्होंने कहा था, लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ। अब उस में सत्ता का लालच रहा हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन गांधी जी की यह बात स्वीकार नहीं की गई। आज वही स्थिति पैदा हो गयी है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने क्षेत्र का विकास अपनी तरह से चाहती हैं, अपनी संस्कृति, अपनी तहज़ीब, अपनी life style की सुरक्षा चाहती हैं। उन्हें वह आजादी मिलनी चाहिए क्योंकि हमने अपने लोकतंत्र को संघीय स्वरूप दिया है, लेकिन जब राजनीतिक गैर-बराबरी होती है तो फिर याद रखिएगा लोकशाही में खास तौर से जो हमारा संघीय ढांचा है, उस पर बहुत आक्रमण होता है। क्या यह गलत है कि राज्यपालों का प्रयोग हथियार के रूप में विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए किया गया है? महोदय, मैं नाम नहीं लेता कि किस पार्टी ने किया, सभी ने किया। जो केन्द्र की सत्ता में रहे हैं, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सियासी गैर-बराबरी उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस से हमारा संघीय ढांचा खत्म हो जाएगा। महोदय, राजीव शुक्ल जी चले गए, वह कह रहे थे कि जनेश्वर जी ने यह कहा। जनेश्वर जी ने कुछ नहीं कहा। जनेश्वर जी ने कहा कब तक पीछे पड़े रहो।

महोदय, एक बार यू०पी० में राष्ट्रपति शासन की चर्चा चली और राष्ट्रपति शासन की बात इसलिए खत्म हो गयी कि इलेक्शन आ गए। अभी कह रहे थे कि ज्यूडिशियरी में सुधार होना चाहिए। सुधार का आधार यही बता रहे थे कि ज्यूडिशियरी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गयी है, विश्वसनीयता खत्म हो गई है। तो एक तरफ विश्वसनीयता खत्म हो गई है, तो अगर हमको यह लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन नहीं प्रयोग कर पाए, तो ज्यूडिशियरी का तो हम नहीं कहते, लेकिन यह जो जजमेंट है, वह संदिग्ध है और सी०बी०आई० पर बात किये। अभी यह बात कर रहे थे कि सी०बी०आई० की कैसे हो सकती है।

आदरणीय महोदय, आज ही के एक अखबार में एक बड़ा आर्टिकल निकला है। यह इतना बड़ा आर्टिकल है - Weapons of Mass Destruction. इसमें श्री अरुण जेटली जी ने 7 एग्जांपिल्स दिए हैं, जहां सी०बी०आई० की भूमिका संदिग्ध रही है। इसलिए हम यह मानते हैं कि सी०बी०आई० की भूमिका संदिग्ध है और हम नहीं चाहते हैं। इसमें हमको साजिश लगती है कि कांग्रेस यू०पी० में राष्ट्रपति शासन इस्तेमाल नहीं कर पाई, हम पर थोप पाई, तो उन्होंने सी०बी०आई० के बहाने से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उनको किसी तरह से एक बहाना मिल जाए। इसलिए अगर हम यह कहते हैं कि सी०बी०आई० के बजाए किसी और से जांच करवा ली जाए। आप कोई संसदीय समिति

बना दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वह एक व्यक्ति का बिल्कुल झूठा आरोप है। उस बात की हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने वह सी॰डी॰ भी माननीय सभापति जी को दे दिया। उन्होंने कहा था कि हमने उसे पढ़ा और अगर हमें लगा कि इसमें कुछ बात है, तो हम कुछ करेंगे, लेकिन वह बात अभी आई नहीं है। जिसमें साफ कहा गया, जिस आदमी ने मुकदमा दायर किया है, अपनी आवाज में वह कहता है कि इन जजेज़ को भी आगे छत चाहिए। हम कभी किसी जज के ऊपर, मैं जानता हूं कि वह हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम जजमेंट पर तो शक कर सकते हैं। नहीं तो फिर किस बात पर बहस हो रही थी कि ज्यूडिशियरी में सुधार होना चाहिए? किस क्रेडिबिलिटी की बात की जा रही थी? इसलिए इसको मैंने कहा कि यह सियासी गैर-बराबरी है: हम जब तक आपको समर्थन देते रहे, तब तक हम बहुत अच्छे थे और समर्थन लेने के बाद हम में सब खराबियां पैदा हो गईं। जैसे ही हमने विदड्रॉ किया, हम राष्ट्रपति शासन के भी योग्य हो गए, हमारे पीछे सी॰बी॰आई॰ भी लगा दी गई। यह मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे प्रयास इस संघीय ढांचे के लिए, प्रजातंत्र के लिए और लोकशाही के लिए बहुत खतरनाक हैं, इनसे बाज आया जाए। मैं यही बात कहना चाहता हूं, माननीय महोदय।

साहब, एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैं कहने वाला था यह सब तो मुझ से जबरदस्ती कहलवा दिया गया। यह तो यह हुआ कि ...(व्यवधान)... मुझे एक शेर कहना पड़ता है, अलका जी ...(व्यवधान)... अलका जी, मैं आपके लिए एक शेर पढ़ रहा हूं ...(व्यवधान)... अलका जी, मैं आपके सम्मान में एक शेर पढ़ रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: यह आपके बारे में शेर कह रहे हैं, सुनिए। ...(व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह: मैं आपके सम्मान में एक शेर पढ़ रहा हूं-

क्या मेरी जुबां पर भी जादू तेरा चलता है,
क्या सोच के आया था, क्या मुंह से निकला है। ...(व्यवधान)...

मैं यह कहने के लिए बिल्कुल नहीं आया था। आप आदरणीय बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि कर्ण सिंह जी ने प्रस्ताव किया, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता था। यह मैंने कहा। अब जो एक-दो बात मैं कहने आया था, वह अब सुनिए। यह तो जबरदस्ती की बात हो गई।

माननीय महोदय, जब हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे और उसमें यह कह रहे थे कि यह देश एक बहुभाषी देश है, बहुधर्मी देश है। उसमें एक एकता और अखंडता का सपना देखते हैं तथा 15 अगस्त और 26 जनवरी को कसमें खाते हैं। लेकिन एक और विषमता बढ़ती चली जा रही है और वह है - शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा में जितनी धाराएं निकल रही हैं, उन धाराओं को मिलाना बहुत कठिन है। ''हिन्दू-मुस्लिम-सिख-इसाई, हम चारों हैं भाई-भाई'' यह कहना बहुत आसान है,

लेकिन एक पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चे को और एक गांव के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे की संस्कृति को मिलाना बहुत मुश्किल है। यह भी हमारी एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। यह इतना खतरनाक है कि मैं आपसे कह नहीं सकता। अभी इस सम्बन्ध में तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि शिक्षा होनी चाहिए और सब के लिए शिक्षा हो। हमारे एक साथी ने भी कहा कि सर्व शिक्षा अभियान की जगह यह ''सरल'' करिए। इसको सरल करिए या न करिए, पर इसको सार्थक करिए। स्थिति यह है कि आप गांवों में चले जाइए तो टाट नहीं, पट्टी नहीं। जब से यह ''मिड डे मील'' आ गई है, तब से बच्चों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन उसी वक्त तक, जिस वक्त खाने का वक्त होता है। उसके बाद तक तो उनके मां-बाप भी आ जाते हैं। उसके बाद वे भी चले जाते हैं और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं। दिन-भर खाना बनता रहता है। जो कुछ भी पढ़ाई-लिखाई होती थी, वह भी चौपट हो गई। इसलिए कि इस मुल्क के अन्दर पब्लिक स्कूल की पढ़ाई दूसरी, केन्द्रीय विद्यालय की पढ़ाई दूसरी, प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई तीसरी और प्राइवेट स्कूलों में भी अमीर स्कूलों की और गरीब स्कूलों की पढ़ाई अलग, गांव की पढ़ाई अलग और शहर की पढ़ाई अलग। आप एकता और अखंडता की बातें करते हैं। पब्लिक स्कूल, देहरादून से पढ़ा हुआ एक मिनिस्टर और दूसरी तरफ एक गांव के, बिहार के रघुवंश प्रसाद सिंह जी, इन दोनों की संस्कृति में इतना अंतर है कि पहले वाले तो कभी हिंदी नहीं बोलते और एक हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी हैं, जिनकी मैं तारीफ करता हूं कि वे अंग्रेजी नहीं बोलते। मैं अंग्रेजी का लेक्चरर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं पार्लियामेंट में आया, तो हमारे नेता ने हमें कहा था कि जिस भाषा में वोट मांगते हो, उसी भाषा में बोलना, क्योंकि हम वोट अपनी भाषा में मांगते हैं। मैं सारी भारतीय भाषाओं का बहुत-बहुत सम्मान करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नर साहब ने पिछले समय में कह दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कह दिया कि अंग्रेजी पढ़ो और आगे बढ़ो। तब वहां झगड़ा हुआ। ज्ञान आयोग की बात कर दी और अभी पीछे कह दिया कि संस्कृत पुराने युग की भाषा है और न जाने क्या-क्या कह दिया, जिससे दंगे हुए। मैं दंगे-फसाद की बात नहीं कर रहा। यहां डा॰ कर्ण सिंह जी बैठे हैं, जो संस्कृत के इतने बड़े विद्वान हैं, बताएंगे कि क्या मैं गलत बात बोलता हूं कि अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है?

श्री उपसभापति: नहीं, गवर्नर को हम डिसकस नहीं करते, उसको रेस्ट्रेन करते हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह: नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैंने पहले ही कहा, लेकिन उनके भाषण पर तो बात कर सकते हैं।

श्री उपसभापति: नहीं, उनके भाषण पर नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह: चलिए, मैं नहीं कर रहा।

श्री उपसभापति: अब कैसे नहीं कर रहे? ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, रूल ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, आप बैठिए। वह रूल है, कैसे है, आपको रूल समझाना पड़ेगा। आप बैठिए। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, आप बैठिए।

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, ऐसा है कि मैं डा० कर्ण सिंह जी से अपील करता हूं कि वह फैसला कर दें कि क्या मैं गलत कह रहा हूं कि अधिकांश भारतीय भाषाओं की मां संस्कृत है? इसलिए जब कोई संस्कृत का अपमान करता है, तो हमें लगता है कि भारतीय भाषाओं का अपमान एकसाथ हुआ है।

उपसभापति महोदय, मैं शिक्षा की बात कर रहा था। गांधी जी ने एक बात और कही थी कि इस देश से अंग्रेज चला जाए, तो देश आजाद नहीं होगा अगर अंग्रेजी और अंग्रेजियत नहीं गई। क्या अंग्रेजी और अंग्रेजियत इस देश से चल गई है? संसद में बात करके देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे अभी अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं गया है। तो गांधी जी का वह सपना अभी पूरा नहीं हुआ, शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज चला गया, तो भी वह मुल्क आजाद नहीं होगा, अगर अंग्रेजी नहीं गई। आज भी हाल यह है, मैं अंग्रेजी का लेक्चरर रहा हूं, एक समाजवादी संकल्प के तहत भारतीय भाषाओं के लिए मैंने दुनिया के सारे देशों में काम किया है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं यहां राजधानी में बैठकर हिंदी का अखबार मांग लूं, तो आसपास के लोगों को यह शक जाहिर होता है कि यह बिना पढ़ा-लिखा आदमी कहां से राजधानी में आ गया है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) पीठासीन हुए]

महोदय, इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बातें हुई हैं, बहुत-बहुत विषयों पर बातें हुई हैं और वह शिक्षा को लेकर हुई हैं।

महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं आपकी निगाहों से समझ रहा हूं, जो आप कहना चाह रहे हैं। जब महंगाई पर बात हुई, तो सरकार ने अपनी पीठ अपने आप ठोक ली कि यह सेन्सेक्स बढ़ रहा है, तमाम विकास दर बढ़ रही है और जब महंगाई की बात आई, तो कहा कि यह इसलिए बढ़ रही है कि सेन्सेक्स से पैसा ज्यादा हो गया है, तो आदमी ज्यादा चीजें खरीदेगा और इसमें चीजों की कमी हो जाएगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़े या घटे, मगर हमारी जो चिंता है, वह यह कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका नुकसान और लाभ सबको बराबर होना चाहिए। हो क्या रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान जो पिछले पचास साल से अनाज पैदा कर रहा है, आजादी के बाद हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार कभी आएगी, मगर सरकार आपकी ही थी, इनकी भी नहीं थी और जबसे आजादी मिली है, तब से बराबर यह हो रहा है कि किसान जो चीज पैदा करता है, उसके दाम ऐसे बढ़ते हैं, जैसे कछुए की गति से बढ़ रहे हों। मैं उदाहरण देता हूं कि सन् 1947 में एक रुपए का तीन सेर गेहूं

मिलता था, आज आठ रुपए मान लो, तो उस हिसाब से 24 गुना भाव बढ़ा, लेकिन सीमेंट की बोरी उस समय जो बारह आने की मिलती थी, वह तीन सौ रुपए में मिलती है, ...(व्यवधान)... जो भी हो, ढाई सौ की मिलती है तो ढाई सौ के हिसाब से भी देखें तो कितने गुना कीमत बढ़ी है।

महोदय, बचपन की एक कविता मुझे याद है -

बच्चो सुनो मिठाई वाला,
आया है मटरू लाला।
लिये हाथ में एक थाली,
इसकी धोती कितनी काली।
इसके डंडे में है फेर,
आने की देता दो सेर।

एक आने की दो सेर मिठाई आती थी, यानी आज के हिसाब से एक रुपये की 32 सेर मिठाई। आज के जमाने में 32 सेर मिठाई कितने की हुई? 3200 रुपये से कम की नहीं हुई। इस तरह मिठाई के दाम 3000 गुना बढ़ गए हैं, सीमेंट के दाम 200 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन पिछले 50 साल में गेहूं के दाम केवल 24 गुना बढ़े हैं। जो कुछ किसान पैदा करता है, उसकी चीज़ के दाम कछुए की रफ्तार से बढ़ते हैं और जो वह ख़रीदता है...।

कुछ दिन पहले जब इस विषय पर यहां बहस हो रही थी, तब माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कंज्यूमर है, उसे भी गेहूं तेज़ न मिले, इसलिए हम गेहूं के मूल्य पर नियंत्रण रखते हैं। मुझे अभी उनके शब्द अच्छी तरह से याद नहीं हैं, लेकिन भाव अवश्य याद है, यहां कृषि मंत्री जी ने अपने एक उत्तर में यह कहा था। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसान से बड़ा इस देश में न कोई कंज्यूमर है और न ही उससे बड़ा कोई उत्पादक है। वहीं सबसे बड़ा उत्पादक है और वहीं सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इसलिए क्या आप उसके हितों का ध्यान नहीं रखेंगे? इन्हीं चीज़ों की वजह से आज ये आत्महत्याएं हो रही हैं और किसान दिन-पर-दिन गरीब होता चला जा रहा है। हमारे सत्ता पक्ष के लोगों की आंखों पर जो चश्मा लगा है, मैंने अपने कानों से उनको यह कहते हुए सुना है कि किसान के पास तब साइकिल नहीं होती थी, आज मोटर साइकिल है, तब उसके पास झोंपड़ी नहीं होती थी, आज पक्का मकान है। अरे, आप अपनी तरफ भी तो देखिए कि तब एमपीज़ कैसे रहते थे और आज कैसे रहते हैं।

देखिए, मैं यह बात तो कहूंगा, जो भी आदर्शवाद है, वह सारा-का-सारा क्या सिर्फ किसान के लिए है? इस देश में नारा दे दिया जाता है, ''जय जवान-जय किसान''। मैं कहना चाहता हूं कि यह नारा एक ही परिवार के लिए है, किसान के बेटे का नाम जवान है और जवान के बाप का नाम

किसान है। इन दोनों के लिए एक ही नारा दिया जाता है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक किसानों के उत्पादन का उन्हें सही मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक तो यह वैसी बात होगी कि आप पत्तों में पानी दे रहे हैं, पेड़ में नहीं। आप पेड़ की जड़ में पानी दीजिए।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं, वह बात तो खत्म हो गई थी कि हमने केन्द्र सरकार से कहा कि हमें यू.पी. में कुछ पैकेज दीजिए, हम ये-ये कार्य कर रहे हैं तो वे कहने लगे कि नहीं, वे सब काम तो हो गए हैं। अब कितने हुए हैं, कितने नहीं, यह अगले चुनावों में पता चल जाएगा, आपका सरप्लस बजट है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सियासी गैर-बराबरी की बात-चीत चल रही थी, उस पर राजीव जी इतने चहक रहे थे, उस तरह की गैर-बराबरी भी बहुत है। उत्तर प्रदेश के साथ यह जो हुआ है, उसके बारे में मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री बनवारी लाल कंछल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने टेबल ऑफिस में बार-बार यह आग्रह किया है कि मुझे कार्यवाही हिन्दी में भेजी जाए, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आज साल-भर हो रहा है, मुझे हिन्दी में कार्यवाही भेजी नहीं जाती है। मेरी शिकायत दर्ज की जाए और इसका समाधान किया जाए।

श्री अमर सिंह: सर, यह बहुत गंभीर मामला है कि अंग्रेजी में कार्यवाही भेजी जा रही है, सर हिन्दी में आनी चाहिए।

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): टेबल ऑफिस इसके बारे में जरूर नोट लेगा और यदि इसमें कहीं कोई कमज़ोरी है तो उसे देखा जाएगा।

श्री बनवारी लाल कंछल: सर, पूरी कमज़ोरी है, यह कोई थोड़ी कमज़ोरी नहीं है।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, I thank you for giving me the floor, at least, on the fourth day of the discussion on the Motion of Thanks moved by hon. Dr. Karan Singh.

Sir, on the question of population, Dr. Karan Singh himself added a rider without proposing a specific amendment, and, I think, I could not be following a better example than that.

Sir, on the 23rd of February, sitting in the Central Hall, I was a witness to the President walking in the panoply, and the Majesty of the President of India giving a speech, and I was wondering how lucky India has been in

getting one President after another, the whole range of them, all learned men of high moral stature who have guided the destiny of this country. Sir, I was particularly impressed by the Address that the President gave midway between the rule of the UPA Government which has actually given us an opportunity to have a discussion of the kind that happens only at the time of a vote of No Confidence except that there will be no vote at the end. So, without any political strings attached to it, so many Members have taken part in it, and they are expressing, they are writing a kind of confidential record of the UPA Government over the last three years.

Sir, the President is aware of all kinds of things, not that these suggestions that we make are not known to him. In the old days, in the British days, the Governors and the Vice Roys did not have advisors There were remembrancers. The idea was that there was nobody good enough to advise a Governor or a Vice Roy. The job of the remembrancers was just to remind them. They knew everything; but they had only to be reminded. So, my speech would be in the nature of a remembrancer, who would only very humbly point out to the President that there are certain notions that are used by the existing Government which need to be reconsidered in all humility.

The first point with which we start is, as in the Address, the President has also expressed his satisfaction about the rate of growth that we have attained. Dr. Karan Singh also referred to that and pointed out that there used to be a sort of threshold growth rate of three per cent which was called the Hindu rate of growth, and he wondered what would be the correct nomenclature for the rate of growth that we are observing today, that is, eight per cent, nine per cent and 9.2 per cent! Sir, I would like to point out that this is not something that has happended under a Sikh for the first time. The rate of growth attained even during the NDA regime was, on an average, eight per cent and in the last quarter of the NDA rule we had actually reached 10.3 per cent, which has not yet been reached under the UPA regime. The credit for this growth does not go either to the UPA or to the NDA. The credit, if at all you want to give it, goes to Mr. P.V. Narasimha Rao and his Finance Minister, Dr. Manmohan Singh. He gets the credit as the Finance Minister then, and not as the Prime Minister now, He broke the shackles that were imposed by the Nehruvian socialism and made the entrepreneurs free. The Indian Entrepreneurs was able to assert himself and he showed after that his capacity to work, his capacity

to take risks and his capacity to innovate, and since then we have had an entirely new paradigm in which eight per cent or nine per cent is becoming possible. No Government can really claim credit for that. The rate of increase of GDP depends directly on the abstinence of the Government from discouraging farmers, discouraging the producers. The figures of 9.2 per cent, etc., have to be understood only in that context. I have to point out, at the same time, that there is no explanation as to why the rate of agriculture growth is only 2.4 per cent. That is a very serious matter and I wish the President had elaborated on that and expressed some kind of a commitment on behalf of his Government as to what they want to do. It is a known fact that in the recent eyars, when the Prime Minister went to Vidarbha, as a great and eminent economist, he should have no problem in finding out what the causes of indebtedness of farmers are. After going to Vidarbha, he appointed a committee. It is still to submit its report. That is a very serious matter. The President of India should have given a firm commitment that even if the Prime Minister's package has failed, his Government will certainly do something so that, at least, the rate of suicides of farmers does not increase hereafter.

Sir, the second point that I would like to mention is about inflation that has been preocupying the minds of everybody. Unfortunately, the President, as also the Finance Minister, appeared to put the blame for this inflation on supply constraints. They are tyring to, particularly, point out that the prices of agriculture commodities have incrased more than the prices of the industrial or secondary commodities. Sir, I would like to very humbly point out to the President that never in the history of independent India have the commodity prices been a cause of inflation. It has always been the other way round. Hon. Uday Pratap Singhji was saying that if the commodity prices had increased by 24 times, the other prices had increased by 150 times or 200 times. In this particular case, I would like to very humbly submit that the inflation that we are seeing today is an inevitable consequence of what is called the *aam admi* economy, the welfare economy.

The Budget goes on spinning out thousands of crores of rupees, and when that kind of money is flushed into the economy, then, the welfare economy, or the kind of that is being following by the UPA Government, inevitably causes inflation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I will have to very humbly submit that the House is adjourned for lunch till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock,

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.]

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Joshi, please continue your speech.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Thank you, Mr. Vice-Chairman.

Before the lunch break, in the two minutes that I got, I submitted for the attention of the hon. President of India that the advice that he has received about the rate of growth is incomplete, and the reality is quite different. I was point out that even the advice about inflation is not correct in the sense that agricultural commodities have never been responsible for inflation. And, this time too, it is not the prices of agricultural commodities which are responsible for the rise in prices. What has happened is, in the spate of populism, so much money is being spent that the banks and the whole country are flushed with money and that is the reason why the prices are increasing. I would also like to submit that this psychosis caused by the rise in prices is being used to do further injustice to farmers who are already on the threshold of committing suicides. The Government has already taken steps to inform private traders in Punjab and the wheat-producing States that they should not enter the market unitil the FCI has had its fill.

Now, recently, the Finance Minister also announced that the Futures Market would not be availabe for wheat and paddy. Sir, this is a trespass on the freedom of market of farmers and I would like to advise the President that this is a matter in which his Government is taking wrong steps.

Sir, the third point on which I would like to make a submission to the President is that he has talked very specifically about the inclusive infrastructure of social and economic development. I would like to point out, Sir, that this inclusiveness is rather spurious and selective in the sense that

it includes the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes communities, it also includes the minority community; it includes even the physically handicapped; it includes women; there would be separate statements in the Budget and there are separate statements even in the President's Speech; but, there is nothing like a separate statement or a chapter for the farmers. So, this selectiveness acts in such a way that those who are born into certain communities are treated as 'included group', while those who have become poor or backward by their vocation have been excluded.

Sir, a number of Members have talked about the inefficiency of the National Rural Employment Guarantee Scheme. As the Scheme started in Maharashtra, I would like to point out that this flagship of the UPA has capsized in the sense that they have not been able to spend the money, the employment offered is barely 37 days per family, and further it is having an adverse effect on the agricultural operations because those who want to work in agriculture prefer to go on the NREGP schemes where they get forty rupees for doing no work rather than go to the back-breaking work in the field where they get fifty or sixty rupees. This is spreading a kind of an immoral environment in the countryside as regards the agricultural labour.

Sir, the last and a very small thing. I would like to mention is the wrong advice he has received about ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please don't stand like that.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, in paragraph 23 of the President's Address, there is a mention of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management proposed to be set up. Now, I would like to say, Sir, that the CFTRI in Mysore does precisely the same work, and possibly, the President has not been told that there is an institute which already exists in the country to do precisely the same work. Sir, with these three-and-a-half points, I complete my humble submission to the President to take note of the situation, particularly because I said this is some kind of a mid-term vote of confidence without a roll call. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Syed Azeez Pasha, not here. Shri Tarlochan Singh.

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा): चेयरमैन सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दे रहे हैं। सर, राष्ट्रपति जी का जो एड्रेस है, उसके पहले पैराग्राफ में एक

बहुत बड़ी गलती है, शायद गलती शब्द अच्छा नहीं है, इसमें इतना बड़ा अन्याय हिस्ट्री से है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि यह साल 1857 की पहली जंग-ए-आजादी का साल है। सर, इस पर मुझे बहुत बड़ा ऐतराज है। इंडिया के जितने भी हिस्टोरियन हुए हैं, जिसमें डा॰ सर जदूनाथ, डा॰ आर॰सी॰ मजूमदार और डा॰ सुन्दरनाथ सेन है, उन्होंने 1857 की घटना के बारे में किताबें लिखी हैं। उनमें से किसी ने भी इसको पहली जंग-ए-आजादी नहीं कहा है। सर, मेरा यह ऐतराज है कि अंग्रेजों का राज 200 साल रहा है, उनसे पहले बहुत से बादशाह रहे हैं, जिनमें बहुत इनवेडर थे। यह जो आठ-नौ साल का पीरियड है.... । इसमें बहुत से ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं थीं, जिन्होंने इस विदेशी राज को उखाड़ने में कुर्बानी दी। शिवाजी मराठा लड़े, जिनकी आज महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि हर जगह पूजा होती है। क्या वे अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे? अगर शिवाजी बगावत कर रहे थे, तो आज उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्या वे जंगे आज़ादी के लिए नहीं लड़े थे? महाराणा प्रताप की गाथाएं सारा देश गाता है। क्या महाराणा प्रताप विरोधी थे या देशभक्त थे? क्या उनका नाम हिस्ट्री में नहीं है? बाबा बंदा बहादुर, जिन्होंने 1709 में नॉर्थ इंडिया में मुगल सरकार को उखाड़कर पहला राज किया। यह नॉर्थ इंडिया में आठ, नौ सौ साल के बाद हमारा पहला सॉवरेन था। यह क्या था? क्या वह बागी था? हम उसे निकालें? मैं यह समझता हूं कि 1857 के लिए यह कहकर कि यह पहली जंगे आजादी थी, आप उन सभी देशभक्तों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी जंग हुई, वह एंग्लो सिक्ख वार है। यह 1845 में हुई थी। इसमें यह कहा कि अगर देश में अंग्रेजों को कभी खतरा पैदा हुआ तो वह उस वार से था। यहां के गवर्नर जनरल को बदलना पड़ा। यह जो अंग्रेज और पंजाब की लड़ाई थी, क्या वह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी? उनको क्या कहें? मेरा यह मानना है कि भारत सरकार किसी और कारण से अपनी हिस्ट्री को गलत न करे। जो हिस्टेरिकल सच है, उसे सही रूप में बताया जाए।

यह कहा गया कि सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह की हम सभी पूजा करते हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन सत्याग्रह के अलावा भी जिन देशभक्तों ने फांसी की रस्सियां चूमीं, उनका क्या रोल है? शहीद भगत सिंह जी का इस साल सौ साल वां जन्मदिन 27 सितम्बर को है, इसमें उसका जिक्र भी नहीं है। हम सभी ने इसी हाउस में यूनेनिमसली पास किया था कि शहीद भगत सिं ी के लिए इस हाउस में कुछ किया जाए। इसी हाउस में, पार्लियामेंट में शहीद भगत सिंह जी ने बम फेंका था। उनका सौ सालवां जन्म दिन 27 सितम्बर को है, लेकिन सरकार सो रही है। क्या शहीद भगत सिंह का देश की आजादी में कोई रोल नहीं है? इसमें हम उन लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी आजादी में इतना बड़ा रोल अदा किया है।

राष्ट्रपति जी के एड्रेस में दूसरी बात सेक्युलरिज्म है। हम सब इंडिया के लोग इस बात को मानते हैं कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह देश शुरू से ही तमाम धर्मों की कद्र करता

है। यह इतिहास में है कि रोम के बाद क्रिश्चियेनिटी सबसे पहले इंडिया में आई। सभी लोग इसकी कद्र करते हैं। यह देखा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म को कौन तोड़ रहा है। हर रोज एक नया नारा देते हैं कि हम सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलर पार्टियां हैं। मैं यह समझता हूं कि उनका जो एड्रेस था, उसमें उन्होंने सेक्युलरिज्म और माइनोरिटीज की बात की है। मैं उसके बारे में कुछ बातें आपके माध्यम से हाउस के ऑनरेबल मैम्बर्स के सामने रखना चाहता हूं। सर, दो साल पहले जब यह सरकार आई थी तो यह एक बिल लाई थी कि नेशनल माइनोरिटी कमीशन को कांस्टीट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। उसका इतना प्रचार किया कि यह ही एक पेनेशिया होगा जब माइनोरिटी कमीशन को स्टेटस मिलेगा तो सारे माइनोरिटीज के काम होंगे। आज दो साल हो गए, वह बिल कहां गया? यह कमेटी के पास भेजा था। कमेटी को भी एप्रूव किए हुए एक साल से ऊपर हो गया, अब सरकार सो रही है। एक तरफ तो हर रोज यह नारा है कि हम माइनोरिटी को यह देंगे, अब दो साल के बाद क्या यह सरकार विदड्रा कर गई, या बिल को लाना नहीं चाहती या माइनोरिटी कमीशन को स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में बात करें।

सर, अभी एक माइनोरिटी मिनिस्ट्री बन गई। मुझे बड़ी हैरानगी है कि सरकार ने माइनोरिटी मिनिस्ट्री बना दी, लेकिन इसमें माइनोरिटीज को क्या गेन हुआ? यह हमेशा कहा गया कि माइनोरिटीज का इश्यू यह मिनिस्ट्री करेगी, लेकिन एक साल हो गया, एक ही खबर पढ़ी है कि अब मिनिस्टर को दफ्तर मिल गया है। बहुत अच्छा ऑफिस मिला है। एक साल की उपलब्धि यह है कि इतना बड़ा लायक मंत्री, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हो, उसे हमने वेस्ट कर रखा है। एक साल के बाद कहा कि उसे दफ्तर दे दिया है। एक साल में मिनिस्ट्री ने काम क्या किया? एक सुपर फलुअस मिनिस्ट्री क्रिएट करके हम माइनोरिटीज को यह बता रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अभी माइनॉरिटी कमीशन भी है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है और सरकार ने 4 कमेटियां बना दी हैं कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगी। पहले तो आप मुझे माफ करेंगे, मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा हूं, मुझ से पहले भी वहां बहुत लायक लोग रहे हैं, पहले तो लोग माइनॉरिटी का मतलब यह समझते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब है एक particular community. पहले एक परदा था, अब सरकार ने वह परदा उतार दिया है, अब वे सीधे एक particular community का नाम लेते हैं।

उपसभापति जी, माइनॉरिटी कमीशन तो है, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है, लेकिन सरकार ने 4 कमेटियां बना दी हैं—एक सच्चर कमेटी, एक जस्टिस मिश्रा कमेटी, एक माइनॉरिटी एजुकेशन कमेटी, एक कमेटी HRD मिनिस्टर के नीचे बना दी कि माइनॉरिटीज़ को और क्या दिया जाए, इस तरह 4 कमेटियां बना दी हैं। दो कमीशन अलग बने हैं और इनको बने हुए करीब डेढ़ साल हो गए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। और बाकी कमेटियों की रिपोर्ट अभी आनी है। मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि सरकार escapism में क्यों believe करती है? डा॰ गोपाल

सिंह कमेटी की रिपोर्ट 1983 में आई थी, जिसने पहली बार बताया कि माइनॉरिटीज़ का भारत में क्या हाल है? उस कमेटी की रिपोर्ट पर एक ऐक्शन तो हुआ और वह रिपोर्ट पड़ी है, उसमें इस नयी कमेटी की रिपोर्ट लगाकर सरकार ने एक काम जरूर किया कि उन्होंने हमारी सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी के मन में ऐसी धारणा डाल दी कि आपको जान-बूझकर पीछे रखा गया है। उन्होंने उनका काम नहीं किया, न ही उसके लिए कोई steps लिए, लेकिन देश में जो community divide की भावना है, उसको ये secularism के नाम पर बढ़ा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि सच्चर कमेटी ने लिखा है, लेकिन क्या कभी हमने compare किया कि भारत में हमारे माइनॉरिटी के लोगों की इस वक्त जो माली हालत है, क्या वह बंगलादेश और पाकिस्तान में है? अगर है, तो बंगलादेशी, भारत में क्यों आते हैं? इसका मतलब है कि यहां जो लोग रहते हैं, वे उन दोनों मुल्कों से बहुत आगे हैं, लेकिन सरकार हर रोज एक ही बात कहती है कि ये लोग पीछे रह गए हैं, इनको आगे करना है। मैं पाकिस्तान born हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी पापुलेशन 5 परसेंट थी और मैजोरिटी कम्युनिटी की 85 परसेंट थी, बाकी हिंदू थे, मैं 1940 की बात कर रहा हूं, लेकिन वहां भी जो हमारा economic pattern था, उसमें हम माइनॉरिटी वाले बहुत आगे थे, क्योंकि ये लोग एजुकेशन में बहुत पीछे थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जितने स्कूल थे, वे सब माइनॉरिटी के लोगों ने खोल रखे थे।। never saw any Islamic school in my district. वहां खालसा स्कूल, गुरु नानक स्कूल, हिंदू स्कूल वगैरह हम लोगों ने खोल रखे थे। तो यह एजुकेशन में जो backwardness है, इसके बारे में हमने कभी सोचा है? यह आज से थोड़े ही है, यह तो कब से चली आ रही है। इसको दूर करने के बारे में HRD मिनिस्ट्री में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी गया था, वहां डेढ़-दो सौ मुस्लिम स्कॉलर्स आए हुए थे। उस सबने कहा कि आप कुआं तो खोद देंगे, लेकिन पानी पिएगा कौन? सरकार को चाहिए कि जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, जितने भी रिटायर्ड जज और अफसर हैं, इस सबकी कमेटी बनाएं। वे लोग अपनी कम्युनिटी में जाएं और बात करें कि स्कूल तो हैं, लेकिन आप लोग पढ़ने क्यों नहीं जाते, drop out क्यों होते हैं? यह काम करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम केवल यही कहे जा रहे हैं कि वे ill—literate हैं।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान से आए थे, उजड़कर आए थे, हमारा सब कुछ वहीं रह गया था और तीन सालों के अंदर हम लोग अपने पांवों पर खड़े हो गए। हमें कोई aid मिली? हमें कुछ दिया? यह जो लाखों-करोड़ों लोग पाकिस्तान से आए, वे कैसे अपने पांवों पर खड़े हुए? आपने हमें कोई रिज़र्वेशन दी, कोई कोटा हमारे लिए था? मैं यह कहना चाहता हूं कि entrepreneurship जो है, यह इंसान की अपनी फितरत है, हमें इसको encourage करना चाहिए, बजाय इसके कि सारे दिन हम यही कहें कि हमें आपको उठाना है, हमने आपको पीछे किया है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में सोसायटी का इस तरह डिवीजन करके हम ऐसी situation create कर रहे हैं जिसके consequences हमें आगे बहुत दिनों तक भुगतने

पड़ेंगे। जरूरत यह है कि जो काम करना है, उसकी पब्लिसिटी कम करो और काम करके दिखाओ, उसके बाद बताओ कि हमने यह काम किया है, लेकिन यह UPA की सरकार माइनॉरिटी के नाम पर राज कर रही है, actually इन्होंने न कुछ किया है, न ही कुछ करने की इनकी इच्छा है, ये लोग सिर्फ स्लोगन बनाने और वोट बैंक जुटाने में लगे हैं। सर, इसके बाद मैं दो-तीन बातें सेकुलरिज्म के नाम पर करना चाहता हूं। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि तब actual practice होती है, वह है इलेक्शन कि हम इलेक्शनों में धर्म के नाम पर वोट न मांगे। इसके लिए पूरी ban हो। हम तो यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जो धार्मिक लोग इसको करते हैं, उनको ban किया जाए। अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ, जिसकी पब्लिसिटी सब लोगों ने देखी। वहां क्या हुआ, बड़ी हैरानगी की बात है कि जिसको हम फिरकू कहते थे, अकाली पार्टी, उसने तो सेकुलर बन कर दिखा दिया कि हिन्दू-सिख unity होगी, तो हम जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, वह धार्मिक पार्टी बन गई और धर्म के नाम पर जो प्रचार पंजाब में हुआ है, उसकी सरकार और तमाम हाऊस के हम जितने मैम्बर बैठे हैं, वे एन्क्वायरी करें। वहां एक धार्मिक डेरा है-सच्चा सौदा नाम का। उससे एक written फतवा लिया गया, एक फतवा निकाला गया कि कांग्रेस को वोट दो। इधर तो हम कहते हैं सेकुलरिज्म, उधर हम सेकुलरिज्म के नाम पर धर्म के लोगों से वोट मांग रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि इलेक्शनों में अगर आप धार्मिक लोगों से जाकर वोट मांगते हैं, तो फिर सेकुलरिज्म कहां रह गया। फिर आप उनको बदनाम करते हो कि वे ऐसा करते हैं।

श्री राजीव शुक्ल: बीजेपी की तीन सीटों के लिए भी सच्चा सौदा ने प्रचार किया।

श्री तरलोचन सिंह: यह पहली इलेक्शन है, जहां अकाली पार्टी और बीजेपी ने कोई धर्म का नाम नहीं लिया। मैं हरियाणा का मैम्बर हूं। कहीं एन्क्वायरी की जाए। पहली बार ये दो पार्टियां पंजाबियत और development के नाम पर इलेक्शन लड़ीं और कांग्रेस पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ी। मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस बात में believe नहीं करता। लेकिन सिख प्राइम मिनिस्टर, सिख प्राइम मिनिस्टर कह कर कांग्रेस ने दिन-रात प्रचार किया, चाहे इतने वोट न मिले हों। लेकिन धर्म के नाम पर प्रचार करने में कांग्रेस सबसे आगे रही। ....(व्यवधान).... ये आपके कहने की बात है, लेकिन जो सच्चाई है, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हाथी के दिखाने के दांत और खाने के और हैं, यह कांग्रेस पार्टी ने अभी किया है, इसके बारे में कह रहा हूं।

सर, दूसरी बात यह है कि हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इज्जत करते हैं। अभी हरियाणा में सिरसा में कांग्रेस की एक रैली हुई। बहुत बड़ी रैली थी। सारी रैली में महात्मा गांधी जी की फोटो के साथ एक इश्तेहार था। मैं बड़ा हैरान हूं कि हम खुद misuse कर रहे हैं महात्मा जी की फोटो का और उनके नाम का और लोगों को कुछ और कहते हैं। अभी हरियाणा में यह एक बड़ी घटना हुई, जिसका जिक्र किए बिना मैं रह नहीं सकता कि यह क्या किया गया।

सर, ऐसा ही रूल ऑफ लॉ की बात है। मैंने एक बार पहले भी इस हाऊस में इसे raise किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह जो पब्लिक सर्विस कमीशंस बनते हैं, यह constitutional provision है। स्टेट में भी बनते हैं, कंट्री में भी बनते हैं। लेकिन मेरे हरियाणा स्टेट में यह हालत है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उससे सारा काम छीन लिया गया। जब से हरियाणा सरकार आई है, उसने पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर रखा है और सारा काम withdraw कर लिया। अब यह किधर की धारणा है? अगर यही सिस्टम चला, तो फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि constitutional amendment करो कि जब सरकार बदले, तो जितने कमीशंस हैं, चाहे वे constitutional हों या दूसरे हों, उनके मैम्बरों को अपने आप resign करना पड़े। यह अभी भी चल रहा है कि कमीशन बैठी है, वे तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन सरकार दूसरी कमेटियों से काम करवा रही है।

सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। मैं एनसीईआरटी के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। पिछले 60 साल से इस देश में एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब सरकार बदले, तो education policy की change का नारा आ जाता है और change of text books की बात की जाती है। हमें यह आज तक समझ में नहीं आया कि हमारी कंट्री इसी का decision नहीं कर पाई कि education policy और syllabus क्या हो और हर बार जब कोई सरकार आए, तो इसी पर नया काम शुरू होता है। जब पिछली सरकार थी, तब उन्होंने टेक्स्ट बुक्स को change कर लिया। यह कह दिया कि उसका भगवाकरण हो रहा है। जब ये आई तो उसको दूर करने के लिए शिकायतें आ रही हैं, तो इन्होंने दूर कर लिया। मैं समझता हूं कि देश के लोग, once for all, यह decision क्यों नहीं लेते कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में क्या हो, हमारी education का syllabus क्या हो। अब जो टेक्स्ट बुक है, उस पर जैनियों ने एतराज किया है कि यह उनके खिलाफ है। सिखों ने एतराज किया कि हमारे गुरू तेग बहादुर जी के बारे में घृणा के शब्द हैं। जाटों ने एतराज किया कि जाटों को लुटेरे कहा गया। फिर किताबें बदल दी गई। हम इनमें provocative चीजें क्यों डालते हैं और सरकार इनको approve क्यों करती है। हमारा जो syllabus है या टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें एक बात हो कि किसी धर्म का प्रचार न हो, लेकिन सब धर्मों के बारे में knowledge हो। सेकुलरिज्म के नाम पर जो basic education है कि मुझे पता हो कि इस्लाम में क्या है, मुझे पता हो कि क्रिश्चियनिटी क्या है, आप यह education तो देते नहीं और यह कहतें हैं कि अगर देंगे, तो सेकुलरिज्म बिगड़ता है। Basic education में यह हो कि every student of India should be aware कि जो पांच बड़े धर्म हैं, इनकी क्या education है। दूसरा, तो हमारा rich heritage है जिस के बारे में दुनिया कहती है कि यह हिंदुस्तान ने दिया, उस के बारे में हम education नहीं देना चाहते। वे समझते हैं कि अगर वह देंगे तो हिंदुत्व आ जाएगा, कभी कहते हैं कि वह किसी धर्म का है। After all हमारा पांच हजार साल का इंडिया है। मैं भी उसी से निकला हूं और आप भी निकले हैं। तो उस rich heritage को हमें

कायम रखना है और हमें उसकी एजुकेशन देनी चाहिए। महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए, आप को धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I was not giving you any signal. I was appreciating your points.

श्री तरलोचन सिंह: सर, आज इस देश को सब से बड़ी जरूरत कम्युनल हॉर्मोनी की है, inter-faith की है। मुझ अफसोस है कि कई सालों के बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए और भी दूसरे लीडर्स आए, सारे दिन मीटिंग चली जिसे होम मिनिस्टर ने conduct किया और फिर सब घर चले गए। सर, सवाल यह है कि जो हमारे inter-faith disputes हैं, वे solve कैसे होंगे? आज यह है कि हर बात कोर्ट में भेज दो, कचहरी जाइए। हम क्यों नहीं iner-faith meetings करते। इस के permanent solution का एक तरीका बनाएं और वहां बैठकर यह decision करें। हम इन disputes से भागें नहीं, कचहरी की shelter न लें क्योंकि वहां तो 20-20 साल उनकी बारी नहीं आती। तो इन्हें उन inter-faith कमेटी में रखा जाए।

दूसरी सब से बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की है। उस के लिए कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। संजय गांधी जी ने यह सबसे अच्छा काम किया था, लेकिन हम वे बातें भूल गए। आज इंडिया में जितने प्लान हम बना रहे हैं, उन को कौन खा रहा है? उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खा रहा है। उस पर हमारा पॉपुलेशन कमीशन बनने से रह गया। एक बात तो हम उस में achievement की बताएं। उस के लिए हम पॉलिटिकल लीडर्स कब इकट्ठे होंगे, कब उस पर फैसला करेंगे? आप चीन की मिसाल देते हो, चाइना में जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गयी है, यूरोप में जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है और हमारी ग्रोथ 28-29 परसेंट है। मैं चाहूंगा कि हम इस के लिए इकट्ठे होकर बात करें। सर, यह बहुत बड़ी बीमारी इंडिया के सामने है। जब तक हमारी पॉपुलेशन चैक नहीं होगी, हमारा कोई प्लान, कोई सिस्टम या कोई स्कीम जनता के लिए कामयाब नहीं होगी।

महंगाई के बारे में बहुत जिक्र किया गया। इस बारे में कल मंत्री जी बोल रहे थे कि हम wheat producting areas, rice producting स्टेट्स का ध्यान रखते हैं। सर, महंगाई separate issue है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन separate issue है। इसे हम mix कर के confuse कर रहे हैं। आज हमारे फार्मर की और भी जरूरतें हैं जोकि महंगाई के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके लिए उन्हें incentive मिलना चाहिए। सर, आज जमीन कम हो रही है, जमीन की capacity to grow कम हो रही है। हमें खुशी है कि former Agriculture Secretary of India, डा॰ एम॰एस॰ गिल हमारे मेंबर हैं जिन्हें इस बारे में सब से ज्यादा knowledge है। सर, हम land का optimum use ले चुके हैं। अब उस में से प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इस के लिए farmer

को incentive की जरूरत है। सर, महंगाई इसलिए भी है कि सरकार की पॉलिसी में हम एक बात रोज पढ़ते हैं कि sensex इतना हो गया। लोग हम से सवाल करते हैं कि यह बीमारी क्या है, यह किसे कहते हैं? हम सैंसेक्स और inflation - इन दो words से छुटकारा ले लेते हैं, लेकिन आम आदमी दाल-रोटी मांग रहा है। सर, आज दाल-रोटी जिस रेट पर पहुंच गयी है, उस में आटा 14 रुपए किलो हो गया है और दाल 70-80 रुपए किलो हो गयी है। सरकार भाग रही है और कहती है कि ''माल आएगा, माल आएगा।'' सर, मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि यह देश का सवाल है। इस में मैं नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी का कसूर है, लेकिन महंगाई कैसे रोकी जाए, इस के लिए सभी पार्टियों को मिलकर joint efforts करने चाहिए। सर, मुझे ख़ुशी है कि यहां रिजर्व बैंक के फार्मर गवर्नर बैठे हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स बैठे हैं, मगर हम लोग जो पीछे बैठे हैं, जो नोमिनेटेड हैं या मैं independent हूं, हमारी बारी नहीं आती because of their excellence in their profession इन लोगों की हमारे सामने special lectures होनी चाहिए। यह बताएंगे तो इस से देश को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। सर, हम others में हैं और others की बारी आती नहीं, लेकिन आज आप की मेहरबानी से मुझे बोलने का टाइम मिला, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। (समाप्त)

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): सर, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं ....(व्यवधान)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Mr. N. Jothi. ....(*interruptions*).... आप बैठिए।....(व्यवधान).... बैठिए, बैठिए।....(व्यवधान)....

श्री राम नारायण साहू:*

THE VICE-CHAIRMAN: This is without my permission. ....(*interruptions*).... Mr. Jothi will start the speech. ....(*interruptions*).... I have not given you permission. ....(*interruptions*).... If you want, I will give you time later. ....(*interruptions*).... Once I have called Mr. Jothi, you cannot speak. ....(*interruptions*).... I will give you time later. ....(*interruptions*).... आप बैठिए।....(व्यवधान).... Nothing will go on record. ....(*interruptions*)....

श्री राम नारायण साहू:*

THE VICE-CHAIRMAN: You cannot speak without my permission. ....(*interruptions*).... Mr. Jothi, please stand up to speak. ....(*interruptions*)....

*Not recorded.

Mr. Sahu, please stop it. ....(*interruptions*).... Nothing will go on record. ....(*interruptions*).... Mr. Sahu, please take your seat. ....(*interruptions*).... This is indiscipline. ....(*interruptions*).... You are a senior Member; don't do that. ....(*interruptions*).... आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो हम टाइम देंगे; लेकिन, without my permission, you canot speak. आप बैठिए ....(व्यवधान). ... Nothing will go on record. ....(*interruptions*).... You don't say anything, please. ....(*interruptions*).... आप बैठिए,...(व्यवधान).... यह क्या indiscipline है?. ...(व्यवधान).... इतने सीनियर आदमी होते हुए भी ऐसा बिहैव क्यों करते हैं?....(व्यवधान).... आप सीनियर हैं, ऐसा क्यों बिहेव करते हैं ...(व्यवधान)... आप बैठिए,...(व्यवधान).... आप बैठिए,...(व्यवधान).... बैठिए, बैठिए।....(व्यवधान)....

Nothing will go on record except Mr. Jothi.

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to speak.

Sir, I would like to touch upon two subjects only. One is about inflation, and the other is about criminal system that is prevailing in our country, the judicial system. Sir, as far as inflation is concerned, it is well proved by the election results and nobody needs to further say anything about that. It is an accepted fact by the Treasury Benches that they lost in two States because of inflation. Sir, we hear, right from the time the UPA Government was formed, certain words like economic buoyancy, jumping, forex, sensex, FDI, GDP etc. These are all catchwords that we hear. But I am reminded of Shrimati Indira Gandhi's period and Shri Rajiv Gandhi's period where the slogan was *garibi hatao,* not forex or economic buoyancy.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: At that time, he was in the Congress. ....(*interruptions*)....

SHRI N. JOTHI: Sir, I want to say certain things. This is an august House, and I am on my legs. Certain words spoken by my political opponents can be removed. It is like casting aspersions on me. I pray that they should be removed. I will leave it to your good sense, but I pray that they should be removed. This is a systematic, calculated campaign against me. This is all political gambling they are doing. ....(*interruptions*)....

---

*Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Do you think that it an aspersion? ....(*interruptions*)....

SHRI N. JOTHI: My father is a district president of DMK party. Then, where is the question of myself being. ....(*interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Do you want to say that this is not a correct statement? ....(*interruptions*).... You can say that.

SHRI N. JOTHI: Yes, It should kindly be removed. ....(*interruptions*).... I deny it. ....(*interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is okay. ....(*interruptions*)....

SHRI N. JOTHI: I will commit suicide rather than joining the Congress Party. ....(*interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is his view. ....(*interruptions*)....

SHRI N. JOTHI: That is my view. ....(*interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is his view.

आप बैठिए....(व्यवधान)....

He has a right to express his view. ....(*interruptions*)....

SHRI N. JOTHI: Sir, I should be allowed to speak. ....(*interruptions*)....

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Sir, he should have committed suicide long back. ....(*interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Jothi, please continue. ....(*interruptions*).... Don't get distracted.

SHRI N. JOTHI: This is a systemic campaign that they are having. Whenever I rise to speak. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please don't disturb him. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Please remember the olden days. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You address the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: You are old enough to remember that. *Garibi hatao,* you said so; I don't understand it. It is too new a Hindi term to understand. *Bikhari* means poor person. *Bikhari* is a description of the Hindi term 'poorest man'. It is 'bhikhari' not 'Bihari'...*(Interruptions)*.. 'Bhikhari' means the poorest of the poor, beggar; then, *daridri.* Instead of economic buoyancy, forex, sensex, I will be happy if our Finance Minister or the UPA Treasury Benches speak about these words, *'Garibi and bhikari'* and *'garibi hatao'.* Let them think about that. Unless they think about that, they are in store for many defeats. The country will also be all right in future. Sir, think about inflation. What steps have they taken to arrest it? Earlier, what was the price of 5 kg of wheat? It was Rs. 50/-. Now, what is the price? It is Rs. 85 to Rs. 90. Earlier, the price of one kg of Edible oil was Rs. 60 to Rs. 70/-; now, it is Rs. 102 to Rs. 110. Earlier, the price of *dal* per kg. was Rs. 30-35/-, now it is Rs. 70-75/-. Like that, earlier, the standard price of vegetables was quoted as per kg. Now, nobody tells about one kg. rate; they tell about quarter kg. rate. Their only index is quarter kg. So, this is the position, Sir. But these people live in Five Star hotels, Seven-Star hotels, they visit foreign countries, talk about aircraft, talk about improvements or modernisation of the airports. Without knowing what is happening in this country, they are talking like this. Sir, there was a joke/cartoon in a Tamil Magazine: "Instead of diamond necklace, a woman, nowadays, wants to have carrot necklace." This is because, nowadays, the price of carrot is more than the price of diamond. This is the cartoon which appeared in the magazine. This is how it is happening Instead of banks being safeguarded by AK-47...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Diamonds are sold per carat; that is why, they are...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Maybe. Instead of safeguarding banks; safe vaults by AK-47, grocery shops and vegetables shops would be safeguarded by AK-47. This is the situation, Sir. This is the level of price inflation. And, what are the steps you have taken? What are the steps you have taken? You have not understood the problem. You have not addressed the problem correctly,

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: He is Whip of the Party, behaving like this...*(Interruptions)*... This is the true behaviour of the Treasury

Benches...*(Interruptions)*... That is the fate of the party, and now, fate of the country...*(Interruptions)*... The UPA Government in the Address gives a new theory on why there is price rise. People have become rich. They are buying more; so commodities available are less, that is why there is a price rise. If you are in darkness, please remain there itself, but, don't bring this country into darkness. What is the issue you are talking about? They say that people's purchasing capacity has increased in multitudes. So, they are buying more, and, since they are buying more, less commodities are available; that is why, there is price rise. We are laughing here, but think about the people who don't have energy to laugh, or, walk about. We must think about poorest of the poor people and not about rich people. Your policy should be guided by poor people, not like this. A very unfortunate situation is now prevailing in this country. There is no check on appreciating inflation. Recently, especially in Tamil Nadu, traders were agitating on one issue, that is, online trade. Online trade is now on the increase. Because of online trade, prices are going up. So many agitations have also been taken up on that, but, nobody is paying any heed to that. The Government seems not to be understanding about that at all. The President in the Address clearly says people have become richer, buying more; that is why, prices have gone up. Online trade is nothing but a gamble. Why are you permitting that gamble? What is the reason behind it? Who are the people who are doing it? That should be addressed. But, unfortunately, our President's Address does not indicate anything about online trading.

Sir, If a man becomes a title thick or a little weighty, it is all right. But if he becomes a *bhootam* or very big, it means there is something wrong. It means, he is suffering from some disease. In the same way, if you say that there is price rise because of the richness, it means there is something wrong in your economic theory. The harvard economists, the global economists, the Reserve Bank economists, all three put together, are now running this Government. All great economists are running this Government. Sir, these economists' running this Government has led to a situation where a common man can't buy vegetables. That is the achievement of the great global economists, the Reserve Bank economists and the Harvard University economists. All these three put together has brought the country to this level. Thank God, only three economists are running this country. Had this figure gone further to four or five, even

water would not have been available for drinking. This is the way in which these real economists are running this country. ...*(Interruptions)*...

Sir, they have no patience ...*(Interruptions)*... They have no patience because ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: He is repeating the same thing. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You please continue. I will protect you. You please continue. ...*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy, you please listen to him and then reply. ...*(Interruptions)*... First you listen properly and then reply. ...*(Interruptions)*... Mr. Jothi, please continue.

SHRI N. JOTHI: A person who can't think further or a person who can't control himself, a person who can't think good will get frustrated. ...*(Interruptions)*... Only those people will get frustrated. This is the frustration, anger. ...*(Interruptions)*... Yes.

Now, Sir, I would come to another subject because my time is very less. The other subject is related to judicial aspect. It is dealt with either in paragraph 44 or 45. There is typical reform. Sir, the other day, Mr. Raashid Bhai, who seconded the Motion, had also mentioned that the number of cases is on the increase. Yes; the cases are on the increase. The courts are not in a position to tackle them. I agree with it. But the cases are increasing for whom? It is for the poor opposition people. There are many ferocious organisations controlled by the Government like the Income-Tax Department. If I do not like an opponent man, let loose that ferocious organisation. It will raid you. These organisations are raiding only the houses of the people of opposition, the houses of the opposition people and not the ruling party people. Let us see the statistics. Let us see the data as to against whom it is done. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Who are these opposition business people? Are they identified? ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Mr. Bagrodia, you are a very senior Member. You know to whom I am referring.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I do not know. Please mention.

SHRI N. JOTHI: I will tell you in the lobby. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: If you are not able to say, then do not mention it. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Now, Sir, since they are asking, I am telling. The income-tax raids are conducted regularly against opposition people like Mr. Amitabh Bachchan. Notices are being issued. And against Ramoji Rao. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): It is political victimisation. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, can anybody imagine ...*(Interruptions)*... the former Chief Minister said that she forget to file her income tax return because...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: The law will take its own course. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Narayanasamy, you can reply. ...*(Interruptions)*... Mr. Jothi, you please continue. ...*(Interruptions)*... Please do not interfere. You can reply later.

SHRI N. JOTHI: I am not saying that the opposition people are above law. But this law is focussed only against them. The law is used against the opposition people.

THE VICE-CHAIRMAN: (PROF. P.J. KURIEN): You are mentioning your point of view. You please continue. You cannot say their point of view. How can you say that?

SHRI N. JOTHI: I have not come across any Congressmen facing any CBI cases. I am saying, it is a shame on that Department. It is a shame on that organisation. The CBI, of course, conducts inquiry and gives the report to you. The CBI is filing cases against the Opposition leaders only. If the Opposition leaders join the UPA, cases against them would be dropped.

SHRI V. NARAYANASAMY: The CBI takes up cases on the directions of the Supreme Court and on the directions of the High Court. He is levelling

charges against the Supreme Court and the High Court...*(Interruptions)*... He is casting aspersions on the Supreme Court and High Court.

SHRI N. JOTHI: My friend does not know...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he is a lawyer by profession and he is charging the Supreme Court and the High Court. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, will you allow the name of CBI to be ...*(Interruptions)*... Will you allow this thing to go on record? Is it parliamentary to talk about the CBI in a derogatory manner?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He is not mentioning any officer...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he is talking about an institution...*(Interruptions)*... It is an autonomous and premier institution. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN: (PROF. P.J. KURIEN): Please. He did not say anything against the Supreme Court...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the CBI is functioning as per the directives of the Supreme Court. *(Interruptions)*

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Sir, he is making his point, let him speek ...*(Interruptions)*... He is always creating disturbances and not allowing Mr. Jothi to speak...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN: (PROF. P.J. KURIEN): No, no. I will control him; why do you do that? I shall control him. You please take your seat.

SHRI N. JOTHI: The CBI is registering cases on its own, just like a police station, and setting the law in motion. My friend, Mr. Narayanasamy, had studied Law long ago, for the sake of attaining a Degree and has probably forgotten it. Anyway, the CBI is another organization that has been set behind the Opposition. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: It is not just against any person,...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN: (PROF. P.J. KURIEN): Please, come to the point. Your time will be over soon.

SHRI N. JOTHI: There are other laws like FERA and FEMA; kindly

have a look at how they are functioning. Who would respect these organizations? These organizations are the arsenal, the weapons in the hands of the ruling party to set right the Opposition parties. If the opposition parties join with them, the cases against them would be camouflaged; they won't move further; somehow or the other, the cases would lose steam in some lower court; no appeal or revision would be made. If a man stands in opposition, against you he would be attacked with all kinds of bows and arrows! This is the level of this Government. What kind of probity has this Government got to stay and proceed further?

Sir, I oppose the way of functioning of this Government. It has no probity; It has no loyalty to the public. It has not got any validity to go any further or run this Government at all. They should quit; they should go. They would not go on their own, but the people would make them go very shortly. the day is not very far. My only request is, my Left friends should rise to the occasion and save the nation. I appeal to them with folded hands, this is the time to think of this country, India, and kindly withdraw your support so that this Government falls and the public has smiles on their faces.

MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): Thank you, Sir. I rise to support the Motion.

After listening to my brother, Mr. Jothi, I feel that he is leaving sarcastic and frustrated. His attitude is one of total frustration. They are out of power for the last so many years and, this time he thought that his leader was coming back to power, but she lost. Now, Mr. Jothi has got no power either in Tamil Nadu or here! so, what can he do? He is totally frustrated. He has to take out his frustration and anger somewhere and that is why he is speaking in this way. ...*(Interruptions)*... When he attended the Standing Committee meeting at Chennai, he said, 'I would not accept the hospitality of the State Government; we go as Members of Parliament'. And he goes out and talks to the Press. He wants to be in the news all the time. That is why, he talks like this. I feel sorry for my elder brother. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Do you mean to say that he does not understand these things?

SHRI N. JOTHI: Are we discussing the President's Address or Jothi's?

MS. MABEL REBELLO: Mr. Jothi, please listen to me.

THE VICE-CHAIRMAN: It is the International Women's Day. Please lsiten to her carefully!

MS. MABEL REBELLO: Sir, the hon. President, in his Address, has said that there is an annual growth of nine per cent during the Eleventh Five Year Plan. But he has also stated that the economic growth is not an end itself. Economic growth is a means and he says that economic growth is meant to create more jobs, distribute the income more equitably across social groups and regions, and liberate the poorest of the poor from the scourge of poverty, ignorance and disease. Sir, this is the sum and substance of the President's Speech. I don't know whether my brother Jothi has really gone into his Speech. He might have read it cursively. But I don't know whether he has done any in-depth study of his Speech. ...*(Interruptions)*... This one paragraph speaks volumes. Sir, India is a country where we are almost 110 crores. India is a very rich country; it is not a poor country. Mr. Jothi has depicted as if we are a third world country. It is not so. It is a very rich country. We are endowed with rich natural resources with different climatic conditions. For 365 days, we get sunlight and we have vast coastlines. Besides that, we have got rich human resource with very intelligent, ambitious and courageous people working hard. Sir, you just look at the world. Mr. Laxmi Mittal has become the steel king of the world. Similarly, Mr. Anil Agarwal, who is in London and is an Indian, has become a non-ferrous metal king of the world. They have made us proud. We are proud of them. A lot of business houses of ours are now buying businesses all over the world. Yesterday only, Tata Steel has bought Corus and they have got all support from shareholders there. ...*(Interruptions)*... I request Mr. Jothi to listen to me. But I do realise that India is rich, but there are lot of Indians who are poor. All of us are aware and lot of people say that 80 per cent of the wealth of India is in the hands of 20 per cent Indians and 20 per cent Indians have 80 per cent of wealth. Similarly, there is a theory that 3 per cent Indians own 60 per cent of India's wealth and 60 per cent of Indians have 3 per cent of India's wealth. I don't know if these figures are true. At least, the first figures are tolerabe, but I don't know whether second figure is true. It is really bad. It is not just UPA is responsible for this. All of us are responsible for this because sometimes or other all of us had been in power. Jothi's party was in power in Tamil Nadu for ages. How is that there are so many poor in Tamil Nadu who go to Kerala and do domestic work there? How is that

so many Tamilians have been settled in Bangalore, as my brother Shri Hariprasad mentioned yesterday? ...*(Interruptions)*... Why couldn't you empower them--socially, economically and politically? Why couldn't you do it? So, somewhere all of us have failed. Not only the UPA, but you also are responsible. Why don't you realise that? Sir, what we need is to bring up people from the morose of poverty. How do we do that? First of all, good education, skill development and employment to our people are necessary. Somebody was saying a few days ago here, Sir, that 50 per cent of India's wealth is in the hands of one community. I don't know whether this statement was made to me by hon. Member of Parliament, is true. I don't know what he is stating is true or not, or whether he has done some research, and after doing some research he has come to this conclusion. This is what is happening. I hope this is not true. Successive Governments have spent multi crores to bring people above poverty line. But what has happened? The benefits have not reached. I agree that the benefits are not reached to the poorest of the poor. Somewhere down the line, our iate Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, admitted that if I send one rupee from Delhi for some district of Jharkhand, Chhattisgarh or West Bengal, only fifteen paise reach into the hands of the poor. This is what is happening. There are many roadblocks, pilferages and slippages. This is where we have to apply our mind; we have to stop it so that the entire money, that is allocated, goes to the cause it is meant for; it is meant for the people. This is not happening. This is a sad thing. Today, Sir, in India, there are almost 70 crore young people below the age of 35 years. This is our fortune; this is our wealth. They are the wealth of the nation. If we can give nutritious food to these people during the formative years and also give them scholarships and stipend so that they can have access to best of the education, then these people can become asset for our country. This is what we need and this is where we have failed.

SHRI N. JOTHI: What is your programme for that?

MS. MABEL REBELLO: I am coming to that. Sir, the programme of *Bharat Nirman* is a laudable scheme. In some States, it has produced desired results like Mr. Jothi's State, his own State-Tamil Nadu. It is doing quite well. Then, Sir, your State, Kerala, has done well. Kerala has got roads. Urban and rural divide has been bridged in Kerala. People in Kerala are educated and most of them are middle class people. But, Sir, maximum poverty exists in the State from which I come. Fifty-four per cent of the

people in Jharkhand, from where I come, are below poverty line as per the Government records. Sir, that is Government record. But, if you ask me, I would say that around 70 per cent people are below poverty line in my State. The project implementation is very poor. Under the *Pradhan Mantri Grammen Sadak Yojana,* Rs. 600 crore, which is due to Jharkhand, is lying here. There is some fault somewhere. The implementing agencies of the State are not able to give even utility certificates and take money from here. Ever since the Jharkhand was formed, for six years, their Government was in power and they could not take the money to implement the development programmes. Money is available, but they could not take the money. Because of their wrong policies, they were not able to implement it and they were not able to produce utility certificates. So, we can imagine who suffers most from this-the poorest of the poor, the tribal people, the person in rural areas for whom this money is meant for, and if these roads would have been constructed with the money that is available to them, which is their due, they would have, by now, improved their quality of life. But, they have failed. Their Government was in power. Similarly, literacy rate in Jharkhand is abysmally poor. The school dropout is 72 per cent. So, one can imagine what happens. Female literacy rate is only 34 per cent. Malnutrition is highest in Jharkhand. Regarding Anganwadi and Mid-day Meal Scheme, I would like to say that hardly 15 per cent of the children get mid-day meal. It has not still been universalised. Most of the tribals, who live in inaccessible areas, do not get benefits of Anganwadi centres at all because it is not physically possible for them to come daily 20 kilometres down to anganwadi centres. Some arrangement has to be made like dry ration can be given to them so that once a fortnight or once a month, they can come and can avail themselves of this scheme. In this way, they will not be deprived of this benefit. Similarly, Jharkhand is the only State where Panchayat elections are never held. There is some problem. Cases are in the Supreme Court. We have not been able to settle it. Because of this problem, this State is deprived of Rs. 350 crores per annum which is due to it. The poorest of the poor people are deprived of this money. Similarly, what is happening? Maximum districts of Jharkhand--20 out of 22 districts--are badly naxalite affected and today I can tell you that almost in every house, either a boy or girl, joins naxalite movement. I happened to ask some of them, why do you do all this. I asked their parents. They said, 'what can we do; we cannot help it'. They replied that they were so poor and miserable that only by joining those

3.00 P.M.

naxalite activities, at least, they could get two square meals. Because of the reason that some amount of money is sent to them monthly, they have joined naxalite movement. This is the problem of unemployment. This is the problem of poverty. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Sir, is she supporting naxalism now? I want to know the stand of the Government ...*(Interruptions)*...

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please. ...*(Interruptions)*... Mr. Jothi, please sit down. ...*(Interruptions)*... She is only saying what people told her. ...*(Interruptions)*... It is a quotation. She is only saying that.

MS. MABEL REBELLO: Sir, there is another problem of law and order. Everybody knows what happened a few days ago. One of our colleagues, a Member of Lok Sabha, was shot dead. All this is happening because of lawlessness. We still do not know as to why it has happened but probably it has happened because of naxalite activity.

Sir, now I come to a very good project of ours initiated by our leader Shrimati Sonia Gandhi, which is her pet project. This project is under the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). Sir, this scheme has been implemented in 200 Districts and almost 1.4 core households have been benefited by this scheme. Almost five lakh works, especially for water conservation and for creating water bodies have been started. In India, our requirement of water is really very huge. Sir, rains here are never regular. Sometimes, there are heavy rains; sometimes, it does not rain at all. For example, the State of Andhra Pradesh suffered from drought for a period of seven years. So, Sir, we definitely need these water bodies, particularly, in the tribal areas and rural areas, where people after one crop, rain fed crop, migrate to urban cities, and, it is good for people who have to lead such sub-human lives. So, Sir, because of implementation of this scheme, it has proved beneficial in so many areas, especially in Jharkhand, Chhattisgarh, tribal areas of Central India, and, migration has declined. So, this is really a useful scheme. If they can get real work for 100 days, and, if they can get work for 100 days in their own forms homes; if they are assured of work for these 200 days, at least, they can lead some sort of human life.

Sir, now, I come to my pet subject, 'Education'. What is happening

today, Sir? Today, Sir, the two schemes, one relating to education and the other relating to Mid-day Meal are two such schemes, in which not only the Government, but everybody wants to invest in. Large funds have been allocated for these schemes. Today, the mindset of the parents is changing. Today, most of the parents--even the drivers or Class-IV servants also come to us--want to send their children to good schools. They do not want to send their children to Government schools. Sir, I can narrate you an incident. Recently, I went to see one of our projects, located deep inside the forests in the tribal areas of Jharkhand. There, the women working in the IFAD project, told me that they have withdrawn their children from the Government schools and were sending them to the private schools. I enquired about the reason for doing so. They said, "अरे मैडम, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं"। What is happening in Government schools? Whether it is in Jharkhand, whether it is in Chhattisgarh, if there are school buildings, there are no teachers. If teachers are there, building is not there. So, children are frustrated, parents are frustrated. I would suggest the Government to encourage public to start good schools in rural areas, in tribal areas and give them grant-in-aid. If they get grant-in-aid, they can run good schools and these children can get scholarships. So, instead of giving money to construct Government buildings and paying teachers, who do not teach, we should do this. We have got to change our mindset, Sir. Similarly, you see in cities like Delhi and Mumbai, what are we doing? We are bringing up two sets of citizens; children going to municipal schools and children going to private schools. At the age of five, when children start going to schools, there are two sets of citizens in India. Why do we have this, Sir? In the years to come, this--two sets of citizens--will definitely hurt the country. I would say even in the municipal schools, we should involve private people and improve the quality of municipal schools and bring these schools on a par with public schools and give our children good scholarships, so that they have an option to go whichever schools they want to go. It should be like that, so that the children do not have a complex. Today, children are suffering. Some children go to Doon and DPS. And other children go to municipal schools. When they play together, one set of children speak English and wear good clothes, and other set of children are poor and live in miserable conditions. With that complex, they grow, Sir. This is not good for us. Children should grow up as children. Some sort of equality should be there while growing up. This is very, very important. But, Sir, my friend, Mr. Jothi, will never understand it.

SHRI N. JOTHI: Sir, I am interested in knowing in which school she has studied, municipal or convent.

MS. MABEL REBELLO: I went to a convent school, Mr. Jothi.

SHRI N. JOTHI: You are a Congress person, naturally ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Yes, that is why I am trying to tell you ...*(Interruptions)*... Let me also tell you that children of drivers and ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA: What is the necessity of talking ...*(Interruptions)*... What is the necessity of calling upon their leader ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Sir, I have not yielded. ...*(Interruptions)*... Sir, I have not yielded. ...*(Interruptions)*... Sir, Mr. Jothi's leader went to a convent school. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, what is the necessity of talking about ...*(Interruptions)*... What is wrong? ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Nothing is wrong. That is why I am saying that everybody should go to a good school. We should not have two sets of citizens. That is what I am trying to propagate, Mr. Jothi.

Sir, there is a large area of Central India where as many as 7 crore tribal people live. They are the ones who are really poor and miserable. They have lost their forest; they do not have land to cultivate. Ninety per cent of them are living on agriculture. Their land is degraded and non-irrigated. Most of them have one acre or two acres of land and it is all rainfed cultivation. They are half-clad and malnourished even today. They live in such inaccessible areas that they do not even have basic facilities like safe drinking water, village roads, electricity, schools, primary health centres, PDS, kerosene, etc. They just do not get them. So much of exploitation is there. Whatever is due to them is taken away from them. Their children are often deprived of mid-day meal and even Anganwadi food supplement because they live in inaccessible areas. Very often they are exploited by the traders. You know, the minute their minor forest produce comes, the traders grab it at throwaway prices or at times they have to pay the loans that they have taken ages ago and they remain throughout their lives as bonded labour. This is the state of affairs.

Similarly, institutional finance just does not reach them. The minute they collect minor forest product, the traders just come and take it out. They cannot keep the minor forest product even for a month. And if they keep it, the traders get the prices depressed. They depressed it so much that they are bound to go for distress sale. All this is happening. Why is it happening? Because they do not have institutional finance. I had raised this issue some time ago when the hon. Finance Minister was here. You know, in the whole country, seven crore tribal people live in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand, and on the borders of Gujarat and Rajasthan, they just do not get institutional finance. They just do not get institutional finance. I think even two per cent of them do not get it. It is very sad to see their state of affairs, the houses in which they live and how they work. And what is happening these days, most of them come here to metropolitan cities as domestic servants and most of them are girls. Recently, one of the Ministers held a meeting here with all the domestic servants who hailed from Jharkhand. Eighteen thousand of them came for that meeting. Eighteen thousand of them attended that meeting, may be a month ago, on a Sunday.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): From only one State!

MS. MABEL REBELLO: They cried and told him their plight. Most of them do not get salary; most of them are exploited; first al all, they get a pittance and they are exploited physically; they are exploited sexually; they are exploited in every way; they are even killed and nothing happens. There is Tribal Atrocities Act and all sorts of Acts are there to protect them, but if they go to police station, nobody lodges an FIR.

Sir, I talked about Chhattisgarh. In Chhattisgarh, there were lot of institutions, voluntary organisations, which are doing very good work, not only today, but from pre-Independence days. Because of the activities of these voluntary people, tribals have become IAS, IPS and all that. But today, the Government of the day of Chhattisgarh for the last 14 months, they are selectively harassing those organisations. That means, they are not interested in helping the poor people. They are not interested to alleviate the sufferings of the poor. They want the poor to remain poor. That is what they are committed to. That is a sad thing. They want these people to remain poor and miserable. That is the problem of the Opposition here. Mr. Jothi has no clue, what is happening. *(Interruptions)* Sir, I am not yielding. *(Interruptions)*

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): सालों आपकी सरकार ने काम किया ...(व्यवधान)... आदिवासियों के लिए क्या किया ...(व्यवधान)... पचास साल आपकी सरकार ने काम किया ...(व्यवधान)...

सुश्री मैबल रिबैलो: ऐसे क्या बोलते हो ...(व्यवधान)... आपको पता है ...(व्यवधान)... Sir, this fellow does not know at all. *(Interruptions)* Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री जयन्ती लाल बरोट: झारखंड में क्या किया ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: आप यील्ड करो ...(व्यवधान)... न करो ...(व्यवधान)... कौन पूछता है ...(व्यवधान)... आप गलत बता रहे हैं ...(व्यवधान)... यह गलत बता रहे हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): मि. पाणि ...(व्यवधान)... आप बैठिए ...(व्यवधान)... आपको चांस मिलेगा ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: आप गलत बता रहे हैं ...(व्यवधान)... सरकार ने सबसे बढ़िया काम किया है ...(व्यवधान)... नक्सलवादी छत्तीसगढ़ में हैं ...(व्यवधान)... ये क्या कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): मि. पाणि ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: इनको रोकिए ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: इतनी देर से हम शांति से बैठे हैं ...(व्यवधान)... इसका मतलब जो मन में आएगा बोलेंगी ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can reply later. I will give you a chance. *(Interruptions)* That is enough. *(Interruptions)* मि. पाणि बैठिए...(व्यवधान)... Please continue.

MS. MABEL REBELLO: Sir, I am not yielding. *(Interruptions)* I mean, just shouting and shouting has got no meaning. *(Interruptions)* I have not yielded. *(Interruptions)*

श्री जयन्ती लाल बरोट: उनको बताइए ...(व्यवधान)... सरकार ने क्या किया है ...(व्यवधान)... देखिए ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is enough. (Interruptions) She is not yielding. Sit down. *(Interruptions)* Now, please continue. *(Interruptions)*

MS. MABEL REBELLO: Sir, what is this? (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उनको कंट्रोल करने के लिए आगे कोई नहीं बैठा है, रविशंकर प्रसाद जी-से कहिए कंट्रोल कर लें...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): आप भी उनको कंट्रोल कर लीजिए, हम भी देख लेंगे।

प्रो. अलका क्षत्रिय (गुजरात): इनको तो कंट्रोल करके खड़ा किया है ...(व्यवधान)... ये क्यों बीच में खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)... इनको तो कंट्रोल किया है ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is enough. You please continue. Please come to your point. (*Interruptions*)

MS. MABEL REBELLO: Sir, they are the exploiters and hoarders and they are the ones responsible to keep a section of our people poor and miserable. I say this with responsibility. And this fellow has the courage to oppose me! Sir, they are responsible for lot of people living subhuman life. *(Interruptions)* Sir, I am not yielding.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. On point of order, you have to yield. (*Interruptions*) What is your point of order?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, sitting in this House, is it fair and just to condemn a State Government? I am asking a question. There are certain rules and regulations. If it is about law and order, if it is about minorities' rights, I can understand. But, in the Motion of Thanks on President's Address, to condemn any State Government, is it fair and just? I am leaving to your kind judgement. My friend is also a senior Member now. She must know the rules of the game. And have a little temper in your voice and a little sobriety in your criticism. That is all I have to say.

MS. MABEL REBELLO: My brother, Shri Ravi Shankar Prasadji, you first tell your colleagues not to provoke me. It is they who provoked

me...*(Interruptions)*... It is my time to speak...*(Interruptions)*... You tell them not to provoke me...*(Interruptions)*... Sir, I am not yielding...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: इस सदन में अगर कोई बैठकर सबसे ज्यादा सुनता है, तो वह पाणि है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): बस-बस, बैठिए ...(व्यवधान)... पाणि जी, बैठिए ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, today is the International Women's Day. Why are they not allowing her to speak?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Today is the International Women's Day. Don't disturb the woman MP while she is speaking.

MS. MABEL REBELLO: My brother, Ravi Shankar, thank you...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please continue.

MS. MABEL REBELLO: So, Sir, my request is, these 7 crore people who live in Central India, who are deprived of the basic amenities, who are poorest of the poor, being poor for the last so many years, and who are still poor, we need to assist them. Most of them live a sub-human life. We need to take special care of them.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Here, I would like to suggest one thing. There has been a special component scheme for the tribals for the last so many years, but it has not yielded the desired results. I would say that all of us have to do some sort of introspection and we need to apply our mind and bring about some innovative schemes to alleviate the sufferings of these tribals so that they can also live a meaningful and quality life. Sir, I am not going to speak much...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to conclude now.

MS. MABEL REBELLO: I am concluding, Sir. I would like to conclude my speech by congratulating the UPA Government for some very bold policy initiatives. For instance, they have passed the NREGA, which is

benefiting the poorest of the poor, and our Government is committed for the poorest of the poor to bring them above poverty line. But, Sir, we have got to apply our mind. A lot of money is available; a lot of projects are available, but the implementation is very, very poor...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to conclude the debate by 4 o'clock. The reply is at 4 o'clock. Please conclude.

MS. MABEL REBELLO: I would request the Government to implement these schemes very effectively so that the benefit of these schemes goes to the poor. Thank you.

श्री उपसभापति: राजनीति प्रसाद जी, आप बोलिए। आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी 3-4 लोग बाकी हैं। वैसे आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): ठीक है, मैं 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री जयन्ती लाल बरोट: आप उधर कंट्रोल करिए, वे 35 मिनट बोली हैं...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मेरा सब पर कंट्रोल है ...(व्यवधान)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: All these parties have exhausted their time, including the Congress Party.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Joshi, the figures are with me, not with you.

श्री राजनीति प्रसाद: उपसभापति जी, मुझे लगता था कि शायद मुझे समय नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लगता है कि पीछे वाले लोग, पीछे ही रह जाते हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि इतने बड़े उच्च संस्थान में जहां मैं आया हूं, हाथ उठाते-उठाते, मेरा हाथ थक जाता है, लेकिन कभी मेरा नंबर ही नहीं आता है, पता नहीं कब नंबर आएगा? अभी मेरा नंबर आ गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी मेरा नम्बर आ गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि यह जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, वह सरकार का नीतिगत मामला है और सरकार आगामी वर्ष में जो करने वाली है, इसमें उसके बारे में रूपरेखा तैयार की जाती है, यह मुझे मालूम है। मैं इस पर बहुत सारी टिप्पणियों में नहीं जाता। मैं सिर्फ दो टिप्पणियों में जाऊंगा, दो पैराग्राफ में जाऊंगा और उसके बारे में इस सदन में मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। वे हैं इसका कंडिका 12 और 14, जिसमें शिक्षा के बारे में लिखा है।

उपसभापति जी, हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे राज्य में पैदा हुए, जहां पर literacy कम है, हम

ऐसे राज्य में पैदा हुए, जहां पर स्कूलों की हालत बहुत खराब है, हम ऐसे राज्य में पैदा हुए, जहां पर सर्व शिक्षा अभियान तो गया, लेकिन सर्व शिक्षा हो नहीं पाई, हम ऐसे राज्य में पैदा हुए। हमारा क्या कसूर था कि हम ऐसे राज्य में पैदा हुए। हमको कभी-कभी लगता था कि कहीं महाराष्ट्र में पैदा हो जाते, तो लोग कहते कि साहब, यहां इतना परसेंट literacy हैं, कभी हमको लगता था कि कहीं केरल में पैदा हो जाते, तो लोग बोलते कि 100 परसेंट literacy है। उपसभापति जी, उसी तरह से इन सूबों का development क्यों नहीं हुआ, यह मुझे समझ में नहीं आता है। महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में और गुजरात में इनकी literacy क्यों आगे बढ़ गई और हमारी literacy क्यों पीछे रह गई, जबकि आजादी के समय हम सभी लोग आजाद हुए थे और पहले सभी लोग गुलाम थे, उसके बाद फिर आजाद हुए। ऐसा क्यों हुआ? उपसभापति जी, इसका मतलब यह हुआ कि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बड़े लोग बड़े होते गए और छोटे लोग छोटे होते गए। जो राज्य किनारे-किनारे बच गए, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उपसभापति जी, इसमें दो अच्छी बातें आई हैं। एक लोअर प्राइमरी स्कूल के बारे में आई है और एक पैराग्राफ 14 में आई है, जो बेसिक शिक्षा है, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में। हमारे देश में एक बहुत बड़े शिक्षाशास्त्री हुए हैं और वे बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं - नुरुल हसन। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष तक अगर...(व्यवधान)...थोड़ा disturbance हो जाता है। हमारी बारी में ही disturbance हो जाता है, यही दिक्कत है। नुरुल हसन ने कहा ...(व्यवधान)...मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता, मैं सुनाना भी चाहता हूं। नुरुल हसन ने यह कहा कि जब बच्चा पैदा होता है और पांच वर्ष तक बच्चों की शिक्षा ठीक से नहीं होगी, तो आगे जाकर ठीक नहीं होगा। यह उनका कहना था और वह चरितार्थ भी है, वह पक्की बात है। उपसभापति जी, आज मैंने अखबार में पढ़ा। सर, मैंने यह पढ़ा कि तीन वर्ष के बच्चे भी स्कूल में नर्सरी में जाएंगे। लेकिन ये तीन वर्ष के बच्चे कहां जाएंगे? हमारी म्यूनिसपैलिटी स्कूल में जाएंगे या जो बड़े स्कूल हैं, वहां जाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे और उन्होंने कहा कि इसे साढ़े तीन साल कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि तीन साल ही रहेगा और तीन साल के बच्चे जब दूध का बोतल लेकर स्कूल में जाएंगे, तो आम लोगों को कौन सा मास्टर मिलेगा। यह दिल्ली के तीन वर्ष के बच्चों के लिए नहीं कहा गया है, पूरे हिन्दुस्तान के बच्चों के लिए कहा गया है। पूरे हिन्दुस्तान के बच्चे नर्सरी में जाएंगे, तो तीन वर्ष में कौन से स्कूल में जाएंगे। वे किंडर गार्टन में जाएंगे, प्रिपरेटरी स्कूल में जाएंगे, बड़े स्कूल में जाएंगे। उपसभापति जी, मुझे मालूम है कि हमारा एक छोटा सा grandson है, वह पांच वर्ष का है। वह बड़े स्कूल में पढ़ता है। मैंने उसको होली के समय कहा कि आपको होली की बधाई हो। आप को मैं होली के अवसर पर congratulate करता हूं। उस ने कहा same to you. वह छोटा लड़का बोला same to you. मैंने सोचा कि same to you उस के पास कहां से आ गया, यह ऐसा विलक्षण कैसे निकल गया? बाद में सोचा कि उस पर दो हजार रुपए प्रति माह

खर्च होता है। उस के मां-बाप दो हजार रुपये खर्च करते हैं, इसलिए उस 5 वर्ष के लड़के ने बोला, same to you. सर मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति है? महोदय, आप ने सर्व-शिक्षा अभियान तो शुरू कर दिया, आप ने मिड-डे मील शुरू कर दिया, लेकिन जो बिहार में स्कूल है या जो अंडर-डवलप्ड स्टेट्स , के स्कूल्स हैं, उन के बारे में कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उन स्कूलों की छत उड़ गयी है, उन्हें बनाने की कोई योजना नहीं है, वहां बच्चों को बैठाने के लिए टेबल-कुर्सी नहीं है। वे छत के नीचे नहीं बल्कि पेड़ के नीचे बैठते हैं। महोदय, मैं आप को बताना चाहता हूं कि उन स्कूलों का क्या होगा, जहां छत नहीं है?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री राजनीति प्रसाद: आप ने सर्व-शिक्षा अभियान तो शुरू कर दिया, नए स्कूल बना दिए, उस के लिए पैसा बहुत गया है, लेकिन जो स्कूल्स पहले से हैं, उन स्कूलों की दशा को भी हम देखें। आप का जो मिड-डे मिल है, उस में मैंने कई जगहों पर देखा है कि वह मिड-डे मील बच्चों को मिलता ही नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां कोई मास्टर पढ़ाने के लिए नहीं आता है। वहां बैठने के लिए जगह नहीं है, बरसात में स्कूल चूता है। अगर बहुत बरसात हुई या बहुत कड़ाके की धूप रही और वहां पेड़ नहीं है, तो बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है।

उपसभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, मगर सरकार को इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप का जो सर्व-शिक्षा अभियान, मिड-डे मील है, और आप के जो दूसरे स्कूल व कालेज हैं, उनके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। महोदय, मैं आप से यह भी कहना चाहूंगा कि आप ने कंडिका 14 में कॉलेज की व्यवस्था के बारे में लिखा है, लेकिन यहां बड़े-बड़े कॉलेज हैं जिन में एडमिशन के लिए लाखों रुपए लगते हैं और यहां छोटे-छोटे स्कूल्स हैं जो एअरकंडीशंड हैं, उन में भी हजारों रुपए एडमिशन के लिए लगते हैं। उन में पैरवी भी चलती है। उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती, इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि उन राज्यों में जहां कि शिक्षा का अभाव है, जहां per capita income कम है, जहां पर foreign investment नहीं है, जहां पर infrastructure नहीं है, उन के बारे में हम लोगों को जरूर विचार करना चाहिए। फिर जैसे आप ने सर्व-शिक्षा अभियान शुरू किया है और मिड-डे मील शुरू किया है, उसी तरह एक अभियान देश में शुरू होना चाहिए कि जो स्कूल टूट गए हैं, जहां कि बेंचे-कुर्सी नहीं हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप को धन्यवाद।

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to oppose the Motion and I have many grounds to do so. First, there is no mention in the Address of reservation for women, either in

legislatures or in jobs. I am surprised there is a demand for 30 per cent reservation for women; whereas, 50 per cent of our population are women. I wish and I demand that political parties should give 50 per cent of the tickets to women. As late Biju Patnaik had reserved 30 per cent jobs for women in Orissa. which is continuing till doay, we should have reservation for women in the Central Government as well as State Governments. I oppose the Motion because there is no mention of what the Government proposes to do to combat inflation. There is no mention of any specific steps to contain inflation. I see some callousness in Govt. saying that supply always takes some time to catch up with demand. Then what is your intervention? Why should there be a Government? I oppose it because there is no mention of how the Government proposes to tackle serious environmental issues which will arise from the ultra mega power projects. As all the power producing States are suffering, at present, from serious pollution, with these ultra mega projects, the situation will become worse. This Address contains nothing about it. There is no mention of how agricultural land will be provided for food security; how they will protect the agricultural land from industries which guzzle too much of land and provide very little employment. Will the Government please consider having some measuring road to measure and identify industries and give those industries priority which are employment intensive? I oppose it because there is no mention of revision of royalty on minerals nor its basis and thus depriving mineral-rich States from coming out of debt trap and ensuring develpment of their poverty stricken people. At the same time, this Government is trying to make money at the cost of the states by imposing export duty on minerals. On iron ore, States get royalty of Rs. 13/- to Rs. 25/-. This Government is trying to impose Rs. 300 per tonne of export duty on iron ore. It is a shameful thing. There is no mention of any special steps for differently abled persons. There is no mention of Paradip of Orissa as a regional campus of the proposed Maritime University, since a Maritime Academy has been running there for the last 15 years. My colleagues from both sides have placed a lot of wisdom on the President's Address and I do not want to repeat any of those arguments. I will confine myself to only serious contradictions which I find in the Address between intentions which are expressed there and the programme of action. In para 3, you difine growth as "a means by which we hope to generate more employment, disribute incomes more eqitably, across social groups and regions and liberate the poorest of the poor from the scourge of poverty, ignorance and

disease". In para 5, you talk of your commitment to inclusive growth and in para 6, you not only talk of faster, inclusive and equitable growth but also of creating productive employment opportunities across the country in all sectors of the economy. Now these are certainly very laudable objectives. Let us see what your Programme of Action is to meet your commitments, particularly to the poorest of the poor, poor regions and the poor social groups like the SCs and STs. Currently, according to the National Sample Survey Organisation, as per the 61st round figures, the highest number of poorest or poor people in rural areas in India is in Orissa, where 57 per cent are earning below Rs. 12 per day and 31 per cent are earning below Rs. 9 per day. Chhattisgarh comes as a close second with 55 percent and 24 per cent respectively. Besides this, Orissa has a large population of poor social groups; that it, 38 per cent of them belong to the SCs and STs. As a region, it is highly underdeveloped in terms of infrastructure, thanks to the persistent negligence by the Cenre over the last six decades. So, as per your commitment in the Address, one would expect Orissa, being the poorest of the poor States, to receive special attention in infrastructure, education, health, allocations for the disadvantaged social groups and a special allocation being a very backward region. What have you done?

You have made a drastic cut in allocation for Railways to thus jeopardishing a very large industrial investment programe amounting from Rs. 41 lakh crores in the private sector in the State. There is also no special allocation for National Highways within the State. A little less than Rs. 100 crores out of more than Rs. 9,000 crores has been made for airport upgradation. Now that is your infrastructure plan for the poorest of the States. And what about education? In para 14, you talk of building new Institutions of Excellence. And for the poorest State of Orissa, having a very large percentage of SCs and STs, you have not only denied any IIT, IIIT and IIMs, but you have also managed to take out the National Institute of Science to the neighbouring State of West Bengal, as a reward to your alliance partner. Your talk of new Central Universities is a sham because for the poorest State of Orissa, you have not only not put up a single Central University in the last sixty years, but you are also trying to deny setting up of a Tribal University, for nearly 1 crore tribal population, which was visualised by late Biju Patnaik in the early 90s.Unfortunately, the Minister of Human Resources Development has denied in a written

reply that there was any proposal for a Tribal University mooted by the Education Consultants of India, a constituent of his Ministry, though I have myself seen the three volumes of that Report. That is the state of affairs regarding infrastructure and education.

Now, Orissa being the poorest State, you should have declared at least 28 out of 30 districts for the Backward Region Grant Fund, applying the same principle as adopted in the case of Bihar. But you have done it only for 19. Not only that you did not do so, but you have added insult to injury by adding 8 KBK districts in the list only with a view to reduce the special allocation which was being given for KBK districts. How much the poorest of the poor in the KBK districts feel insulted by all these deceptive statements your Government has put into the mouth of your Ministers including even the hon. Prime Minister. You did not spare the hon. Prime Minister even, so much for your commitment to the poorest of the poor, poor regions and the poor social groups! As per the Special Package for the districts worst affected by farmers' suicides, which you have stated in para 17, it appears to me that the only way the poorest States like Orissa, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, etc. can attract special allocation is by inducing our poor farmers to commit mass suicides. Perhaps, that will attract your attention. Special packages, special allocations will come; otherwise, no. As for education and health, you are unable to double the three per cent of GDP on education due, perhaps, to scarcity of resources. When you can offer huge tax and duty concessions to industrial houses of the country and from abroad in the SEZs, why do you shy away from giving anything to the poor? And you keep on trying again and again to withdraw subsidies for the poor. If you are not going to make the poorest of the poor the focus of all your programmes, kindly do one thing. Allow entire areas of poor States like Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, etc. to be declared as SEZs so that the poor who are migrating now do not migrate. Their organs can traded; they are being killed and so their skeletons can sent abroad. You want to earn foreign exchange! You can earn plenty foreign exchange and the poor can at least get a reasonable price for their body parts. And you can continue gloating over a below one per cent increase in the allocation for education; you can keep on gloating over creating a National Rainfed Area Authority without examining why ICRISAT failed to deliver; you can gloat over your historic Bill to provide rights of land to STs while you allowed the same

facility to the exploiter non-tribals, who have taken away their lands in valleys and foothills and have then chased them into the jungles and hill-slopes to exploits them further. I am very sorry that is what we have done and you have made us a party to it. You can gloat over unleashing a second Green Revolution without any indication of how to achieve it. You can gloat over having created a law for micro, small medium industries while, at the same time, taking away another large list of items from the reserved list. I am sorry to say that the poor have no pride of place in your scheme of things. You have not cared to talk about the poor village artisans, toy-makers, craftsmen and the like. You would like large houses to spread out to retail trade in rural towns and villages to take away jobs of small shopkeepers and seriously affect the prospects of marketing of lakhs of Self-Help Groups which have been created. Surprisingly, your Allies in West Bengal have signed a MoU with Reliance for retail trade. You want to open the retail sector to FDI. Please state your true intentions in the Address and not shed crocodile tears for the poor. Then, we will understand. You have already wasted three years in only talking about employment. And now you talk of productive employment across regions, across sectors. What is employment? You have given no hope for the educated unemployed. You have given no hope for the rural people. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: What is happening in Orissa? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Mr. Narayanasamy, please. There is no time* (*Interruptions*) Please. We have to complete before 4 o'clock. Please conclude. ...(*Interruptions*)... Mr. Narayanasamy. *(Interruptions)* You please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: नारायणसामी जी, आपके पास जानकारी नहीं है।

श्री उपसभापति: आप बैठिए।....(व्यवधान).. Please conclude.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I have said that Orissa today is the poorest State, with 57 per cent of its people earning less than Rs. 12 per day. And what are we doing? Through this great National Rural Employment Guarantee Scheme, ensuring 100 days' wage employment, all that you are ensuring is an earning of below twelve rupees per day. Please calculate. You are trying to bring all the people in the rest of India down to the level of Orissa.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I have already informed the House.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: I am concluding with one sentence, Sir.

In your quest for vote-bank politics, growth will be for the rich, for the affluent among the disadvantaged and for more affluent regions. With your *one wonders how the poor in this country can ever hope to lead a decent life.

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to express my views on the Motion of Thanks moved by Dr. Karan Singhji. Sir, while delivering his speech before the joint sitting of the Members of both the Houses of parliament, the hon. President has highlighted several major achievements of this Government. The major achievements are: the Right to Information Act, the National Rural Employment Guarantee Scheme, the Scheduled Tribes (Recognition of Forest Rights) Act and then the Central Educational Institutions (Reservation in Admissions) Act which provides for reservation of seats for Other Backward Classes in higher educational institutions. Certainly, these are very laudable. But, unfortunately, there are several failures on the part of the Government. Many of the promises which they have made in the National Common Minimum Programme have not been fulfilled. For example, they have not brought forward the Bill to reserve 1/3rd seats for women in legislatures. They have also not brought forward the Bill to provide for national security to the unorganized labour. I don't know whether the draft Bill is ready or not. So, there are the things which they have not fulfilled. The Budget has also not come up to our expectations. The abnormal price-rise has created a lot of havoc because the hard-earned income of the common man is eroded due to this price-rise. You know that for the past 18 months, there has been 45 per cent rise in prices which is really unbearable. Even though the Government has allocated some funds for agricultural growth; I don't know whether we are going to achieve the target of four per cent growth in agriculture. While we are talking about agricultural growth, we are not addressing the problems of peasants' distress and farmers' suicide. The Government is supposed to solve these problems by taking effective steps. For water bodies, we are taking loan from the World Bank. But, We are quite sure that they are

* Expenged as ordered by the Chair.

going to put certain conditionalities like privatization of water resources and supplies. We should be careful about it.

Now same is the case with education, which has become bad to worse. Now, we are seeing that privatization and commercialization of education is at its peak. Sir, a country cannot advance if the enrolment does not touch 20 per cent. At present, we are seeing that in the age group of 17-23, only seven per cent enrolment is there in higher education, which is not a good sign.

Now, coming to the Sacher Committee's Report, I would like to say that this Report is really an eye-opener which says about the wretched conditions of the Muslim community. Now, the Government is talking about affirmative action. But, unfortunately, this affirmative action is not getting concretized in the shape of giving constitutional guarantee under article 16(4). So, we have to do something in this regard; otherwise, it will also meet the same fate which the Gopal Singh Committee met.

Sir, now coming to the problems of my State, I would like to say that there are several irrigation projects in my State which are pending with the Central Government. Sir, due to regional imbalances, the feeling of separation has creeped into our State. So, I insist upon the UPA Government to taken some major irrigation projects as national projects. Then, there are two-three other problems. Now, we are importing fertilisers from abroad. In my State, the Ramagundam Fertiliser Plant has been closed due to some problems about the pricing policy. So, we feel that there is an immediate need that the Government should correct this pricing policy and reopen the Ramagundam Fertiliser Plant. Now, we have seen that recently a cement plant at Adilabad is also closed. Now, the prices of cement have been really steeping very high and the State Government is ready to subsidise certain things. But we need at least Rs. 40-50 crores for the working capital. The Government should come forward to provide for this working capital for the Adilabad Cement Plant.

Then, in the Railway Budget, we are very sorry to say that Andhra Pradesh has got a very bad deal and all the Members of Parliament represented this matter to the hon. Prime Minister and we requested him to at least give a commitment for the establishment of a coach factory in Khazipet, which is a long-standing demand.

These are some of the issues which I thought of bring to the notice of the House, and before concluding, उदय प्रताप सिंह जी ने कुछ शेरो शायरी का सिलसिला छोड़ा था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी दो शेर कहकर अपनी जगह लेता हूं।

"नोए इंसान में सरमाया व मेहनत का तज़ाद,

अमन व तहज़ीब के परचम तले कोमों का फसाद।

"लहलहाते हुए खेतों पे जवानी का समां,

और दहकान के छप्पर में न बत्ती न धुवां।"

"यह फलक बोस किले दिलकशो सीमी बाज़ार,

और यह गलाज़त के छप्पर तले भूके व नादान।"

यह सभी क्यों है, यह क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आता। शुक्रिया।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to speak. I welcome the Address of the President of India for one good reason. In the Address, the President has declared that this Government attached greater importance to the social justice. Sir, there are also other factors— like the President declared that this Government attached greater importance to higher education in the country, Sir, an assurance is also given—that public finance would be managed with prudence and that the Government had identified factors which were leading to inflation and price rise and the Government's vow to insulate people from being affected by inflation irrespective of the fact there is fluctuation in the oil prices globally.

Sir, it is also heartening to learn that an independent Ministry for Women and Child Development has been created. But, Sir, we are disappointed that reservation for women in the legislation is not declared in this Address of the President. Sir, we, the DMK Party demand that the 33 per cent reservation for women should be made and in that regard, we also conducted a massive rally of the Women Wing of the Party in all the district headquarters of Tamil Nadu. It was a largely attend rally, all over Tamil Nadu, by the women on the 10th February, 2007. All these were conducted by the Party with the legitimate expectation that this announcement would be made at least in this Session of Parliament.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Why do not you insist that in the Cabinet? *(Interuptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. You have to appreciate it,

actually. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI S.G. INDIRA: I am not opposing it; in fact, I am supporting it. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: For the first time, the AIADMK is supporting the DMK. *(Interruptions)*

SHRI N. JOTHI: We are pioneers in this. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please continue, Mr. Shunmugasundaram.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, in Tamil Nadu, there are a lot of investments taking place and there is a tremendous growth in the IT industry. But, Sir, the growth in other sectors is not keeping pace. The IT in Tamil Nadu has recorded a tremendous growth. Sir, in other sectors of education there is not much growth, particularly in science, the basic science subjects. There are no takers for science subjects in colleges and educational institutions. Sir, the Government has announced setting up of the Indian Institute of Science for Education and Research in three places, namely, Kolkata, Chandigrah, and one other place. I demand and I request that one such Institute, the Indian Institute for Education and Research, should be established at Chennai because the basic science is very important. When this Government has assured that highest importance will be given to education, this one aspect has to be looked into. Sir, the President's Address also declared the implementation of the Rajendra Sachar Committee Report. On behalf of the DMK, we welcome this Report because we always support the minorities and, Sir, minorities support us in all our elections. In the last Lok Sabha elections, we were able to win all the 40 seats in Tamil Nadu and Pondicherry. In the subsequent elections to the local bodies... (*Interruptions*)...

SHRIMATI S.G. INDIRA: With the help of so many alliances!...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: The High Court has set aside it ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Our success is 85 per cent in the local body elections ...(*Interruptions*)... We recorded 85 percent success irrespective of somebody approach in the court. ...(*Interruptions*)... The minorities are always supporting us. ...(*Interruptions*)... That is our tradition and that is our culture in Tamil Nadu. Sir, there is no religious disparity against any religious group ...(*Interruptions*)...

4.00 P.M.

SHRIMATI S.G. INDIRA: It is only a minority vote bank. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: All religious groups always live in peace and harmony in Tamil Nadu irrespective of the religious faith they profess. They visit other religious places like Nagore. Nagore is frequented by persons belonging to other religious faith. The same thing happens in religious places like Vellangani and Avadi. These are places of pilgrimage even for those persons who profess other religions. Sir, communal harmony is prevalent. That is why, Sir, we welcome the implementation of the Sachar Committee Report. I have been always telling that had the Babri Masjid been in Tamil Nadu it would not have been demolished. That is the attitude of the Tamils. Sir, we always live in peace. Sir, there is one mention while referring to the foreign policy to Sri Lankan problem. ...*(Interruptions)*... That is a very important problem. It has to be resolved...*(Interruptions)*... And unless it is resolved there would not be...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, Sri Lankan problem has to be resolved through a negotiated settlement.

Sir, with these words, I welcome the President's Address. Thank you.

श्री उपसभापति: चौधरी मोहम्मद असलम। आप दो-तीन मिनट में बोल दीजिएगा।

चौधरी मोहम्मद असलम (जम्मू और कश्मीर): डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि जनाब-ए-प्रेजीडेंट के एड्रेस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और जिसकी तहरीक मोहतरम डा॰ कर्ण सिंह जी ने यहां पेश की थी, मैं उसकी सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जनाब-ए-वाला, प्रेजीडेंट साहब का जो एड्रेस है, अगर इसको बारीकी से देखा जाए, तो इसके अंदर मुल्की, सियासी, मआशी, इक्तसादी सूरतेहाल का जायजा लिया गया है और यह एड्रेस किसानों, मजदूरों और गरीबों का है। प्रेजीडेंट एड्रेस के दूसरे पैरा में उन्होंने फरमाया है, to affect our common quest for normalisation of relations between India and Pakistan.

जनाब, जिस रियासत से मैं ताल्लुक रखता हूं, वह रियासत हमेशा मिलिटेंसी की शिकार रही है। मैं मशकूर हूं, यूपीए सरकार का और खसूसी तौर पर अपने महबूब रहनुमा प्राइम मिनिस्टर डा॰ साहब का, जिन्होंने ऐक्तदार संभालते ही जम्मू और कश्मीर की तरफ पहल की कि किस तरह से रियासत में अमन लाया जाए। यही नहीं, बल्कि यहां तक किया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो

डायलॉग शुरू किए, जो गुफ्त-व-शनीद शुरू की, उसमें भी उन्होंने अपनी ओर से जबर्दस्त पहल की। उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के सदर मुशर्रफ को भी टेबल पर आना पड़ा और बातचीत करनी पड़ी। उसके बाद यहां के लोग वहां गए, वहां के लोग यहां आए, यहां के पार्लियामेंटेरियन वहां गए, वहां के पार्लियामेंटेरियन यहां आए, यहां के अदीब वहां गए, वहां के अदीब यहां आए। एक सिलसिला शुरू हुआ, आने जाने का और बातचीत का। फिर सबसे ज्यादा अहम बात जो हुई, वह यह हुई कि जम्मू-कश्मीर को करीब लाने के लिए रास्ते खोले जाएं, पाकिस्तान-हिन्दुस्तान को करीब लाने के लिए।

[श्री सभापति पीठासीन हुए]

प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहल करके मुज्जफराबाद रोड का इफतिताह किया। उसमें मैं मोहतरमा सोनिया गांधी जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वे खुद भी वहां गयीं और उन्होंने ही उस रोड का इफतिताह किया। वह रोड खुली और पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान आए, हिन्दुस्तान के लोग पाकिस्तान गए। इसी तरह से पुंछ के मामले में जो लोगों की अहम डिमांड थी कि पुंछ वाले रास्ते को खोला जाए। उस रास्ते के लिए भी मोहतरमा सोनिया गांधी खुद वहां गयीं और उन्होंने उन मेहमानों को, जो पाकिस्तान से आए थे, उनको रिसीव किया। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की शांति और अमन की तरफ जो तवज्जह है, वह मुल्क के लिए निहायत जरूरी है। किसी मुल्क की तरक्की, किसी रियासत की तरक्की उस वक्त तक फआल नहीं बन सकती, मुअस्सर नहीं बन सकती, जब तक उस मुल्क में शांति न हो, अमन न हो, चैन न हो। लेकिन आज सूरत-ए-हाल बदल चुकी है - हमारी पॉलिसी की वजह से और डा॰ मनमोहन सिंह साहब की कयादत में इस वक्त हालात बहुत करीब आ रहे हैं और अमन की तरफ आगे चल पड़े हैं। लेकिन किसी मुल्क के लिए इतहाद की बड़ी जरूरत होती है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हालात रहे हैं। अगर हम हिन्दुस्तान की 60 साला सियासी जिंदगी देखें तो हमारा मुल्क मुख्तलिफ हालात से गुज़रा है, मुश्किलात से गुज़रा है। यह मुल्क मुख्तलिफ मज़हबों का मुल्क है, तहज़ीबों का मुल्क है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख और इसाई रहते हैं और इनकी जो एकता है, वह आज तक कायम रही है। लेकिन कुछ बेरूनी ताकतें भी रहीं जो हमारी एकता को, हमारी अखंडता को कमज़ोर करने पर तुली हुई हैं। चुनांचे आज भी हमारे मुल्क के अंदर किस्म-किस्म के सवालात पैदा किए जाते हैं, सिचुएशन को कम्युनलाइज़ किया जाता है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लिए इत्तेहाद बहुत होता है और अगर इत्तेहाद हो तो जो नामुमकिन है, वह मुमकिन हो सकता है और पहाड़ों की जो बुलंदियां हैं, फ़लक की वुसअतों और समुद्रों की गहराइयों के लिए इंसान को मसख्खर कर सकती हैं। इत्तेहाद ही मुल्क का मेन खज़ाना होता है। इस तरफ जो तवज्जह दी गयी है, मैं समझता हूं कि उस वक्त तक ये तरक्की नहीं हो सकती थी। प्रेज़ीडेंट साहब के ऐड्रेस पर बहुत सारे लोगों ने यहां अपने ख्यालात का इज़हार किया है। मैं समझता हूं कि यह काबिल-ए-तारीफ

है, काबिल-ए-सताइश है। मैं उदय प्रताप सिंह जी की नज़र करता हूं:

आइने जवां मरदी, हक कोई व बेबाकी,
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही।
वो दिन गए तनहा था तनहा था,
आज कुछ मेरे और भी राज़दान है।

इन्हीं अल्फाज़ के साथ मैं इस शुक्रिया की तहरीक को पास करता हूं। शुक्रिया।

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, I join all the hon. Members of this House in expressing our deep sense of gratitude to the respected Rashtrapathiji for his inspiring Address which sets out the broad strategies, policies and programmes of our Government, the challenges that lie ahead and the manner in which those challenges can be met and transformed into opportunities for building a new India, free from the fear of want and exploitation. Sir, it does not require much explanation to say that our foremost task is to get rid of chronic poverty, ignorance and disease which still afflict large segments of our population. Great many efforts have been made in the post-Independence period and we have been able to soften the extreme edges of mass poverty. But, it cannot be denied that the task is still incomplete and we have a long way to go before we can get rid of this mass poverty which has been the scourge of our society for centuries.

To do so, we require a rapidly expanding economy. Without a rapidly expanding economy, we cannot find meaningful solutions to the problems of mass poverty, ignorance and disease. Fortunately, the last three years have seen a significant step up in the overall performance and growth of our economy. I will be the last one to say that the growth rate is everything and that it sums up all the features of our complex polity. But it is also a fact that without rapid growth, particularly without rapid growth in manufacturing, we cannot find the resources which we need if we have to devote them, in ever increasing amount, to problems of rural development, to problems of educational backwardness, to problems of ill-health. It is because our economy, in the last three years has grown at a handsome rate of 8.3 per cent that we have, today a situation where that gross tax revenue of the Central Government can go up by as much as 27 per cent. That has given us a new manoeuvrability in devoting more

resources to education, to health, to rural development and for building social safety nets to protect women and vulnerable sections of our society against uncertainties that characterize modern life. Sir, as I said, I will be the last one to say that growth by itself is a sufficient condition for the removal of poverty. We need growth. It is a necessary condition. But, we need much more than that. There must be a purposeful pursuit of policies to focus, particularly for the empowerment of the weaker sections of our society, be they SCs/STs, OBCs, minorities, women and children. We need policies and programmes to empower these sections of our society to become effective partners and effective participants in processes of economic development. We need to focus much more sharply on reducing the regional disparities in levels of development, so that all regions of our country are effective partners in processes of development.

Sir, it goes without saying that in a country where 65 per cent of its population lives in rural areas, the performance of agriculture has a profound bearing on what happens to the average livelihood strategies of ordinary people. I do recognize that in recent years, the performance of our agricultural economy has not been up to the mark. It is certainly not in line with what we need if we have to sustain a growth path which lifts all our people on the route to sustained development. I will touch upon that in a few moments.

Also, Sir, I do recognize that inflation hurts people and it hurts the poor people more than any other segment of population.

We need, therefore, effective strategies to protect poor people against inflation. We need effective strategies to see that inflation do not become a cumulative problem as it has become in Latin American countries and in some African countries. We are fortunately not anywhere in that line. But, we have to be vigilant. We need to do a lot more for agriculture. We need to do a lot more in order to ensure that inflation remains under control. And, the House has my assurance that we will work with determination to ensure that our agricultural economy gets the required momentum. We will make every effort to ensure that inflation is brought under control.

Sir, having said that, I would also like to say that in the long run, in a country like ours, with traditions of settled agriculture for nearly 5000 years and with the growing pressure of population on land, a situation

has arisen where the per capita size of agricultural holdings is getting smaller and smaller. There is considerable scope for improving agricultural productivity through the application of modern science and technology and we must use that knowledge to harness our latent agricultural potential. But, there are limits to which we can increase agricultural income and agricultural productivity, given the small size of our holdings. And, that is why, right from Panditji's times, even before Independence, the National Planning Committee over which Panditji presided, and after Independence the strategy of successive Plans has been, to project a vision of dynamic industrialisation which would involve a progressive diversification of occupation patterns; more people getting out of agriculture into modern industry and modern manufacturing and, thereby, helping to raise the standard of living, both in agriculture and providing gainful employment opportunities outside agriculture. Therefore, we must not lose sight of walking on two legs. Panditji used to say, "Everything else can wait but agriculture cannot wait." And, I endorse that sentiment more so at a time when the growth of our agricultural economy has been a problem for us. But, we must not lose sight of the long-term vision that meaningful solutions to the problems of unemployment, and underemployment in a predominantly agrarian economic like ours can be found only in the framework of a rapidly expanding industrial economy. It is this vision, I think, my friend, the Chief Minister of West Bengal has been trying to project. I think, we must not lose sight of it. There may be particular problems about particular projects, but without rapid industrialisation, I think, India cannot realise its manifest destiny. This is the background, Sir, which I would like to state before this House and this is the background against which our policies and programmes have been formulated.

Sir, I started by saying that the performance of our agricultural economy has not been up to the mark. It is not a problem of one year or two years or three years. Since 1996, the growth rate of the agricultural economy has been declining sharply, and this is a matter of serious concern. The House would, therefore, like to ask me as to what I propose to do to deal with this menace. Sir, It is obvious that if we have to make accelerated progress in agriculture, we need to pay a lot more attention to the problems of water management. We have to pay more attention to expansion of the area under irrigation. Sir, the House has my assurance that this will be an important focus of the Eleventh Five Year Plan, which is going to begin

in a few weeks. Sir, we need a technological breakthrough to improve the productivity of dry-land agriculture. It is only about 35 per cent of the area under cultivation which has the benefit of irrigation. Even when we expand irrigation, I am told it will not be possible to raise the proportion of area under irrigation to beyond 45 per cent. Therefore, a strategy for development of dryland agriculture has to be the kingpin of the new agricultural strategy, and, for that, we have to harness the modern science and technology, particularly, the bio-technology advances, to realise our growth potential in the areas of dryland agriculture. In this context, I would like to mention to the House that recently established National Rainfed Area Authority will attend to the task of revitalisation of dryland agricultural economy of our country on a priority basis. Sir, the House has, many times, discussed the need for expansion of rural credit. The House has my assurance that the need for rapid expansion of institutional credit for our agriculture will be attended to with determination. I recognise that in some parts of our country, indebetedness of farmers constitutes a major burden. I have myself visited some of these distress-prone areas. We have appointed an expert group under Dr. Radhakrishnan to look into this matter on a priority basis. I am waiting for the report of that expert group. We will take speedy action, once that report is available.

Sir, modernisation of agricultural research and extension services should and will receive greater attention than ever before. Districts characterised by agricultural distress have already been identified. Area-specific strategies have been put in place to deal with the problems of these districts. In addition, all these districts, from April 1st, will now be covered by the National Rural Employment Guarantee Programme which will provide a valuable social safety net for the rural poor and the deprived sections of our rural population.

Sir, as the House knows, this programme will now cover 330 districts, that is, more than half the districts in our country. In the Eleventh Plan, our intention is to cover all rural districts of our country under the scheme. Bharat Nirman, a programme designed to develop rural infrastructure with emphasis on irrigation, rural roads, rural electrification, safe drinking water and rural housing will also make a major contribution to improving the quality of rural infrastructure in the next five years. We have since the current year launched a Backward Regions Grant Fund which will focus on improving the quality of rural infrastructure in 250 backward districts

of our country. Sir, my own feeling is that if the programmes that we have identified are well implemented, they will make a handsome contribution to softening the harsh ages of extreme poverty which characterises these districts. Great responsibility rests both on the Central Government and the Sate Governments in inproving the quality of governance and to plug loopholes in the implementation of these programmes.

Coming, Sir, to the problem of inflation, Janeshwar Mishraji and Sitaram Yechuryji referred to this problem, and I share their concern — I am convinced that the measures that we have now put in place, both on the demand and the supply sides, will help us to moderate inflationary pressures in the months to come. Already, since the House met, the inflation index has moved in the right directon and it has, I think, declined by about one percentage point. I would like the House, however, to appreciate that we are trying to curb inflationary pressures without adversely affecting the strong growth impulses which now characterise our economy. We have never had an investment rate as high as 34 per cent of our GDP. We never had achieved a savings rate as high as 32 per cent. There is today a big investment boom going in the economy and if we sustain that boom for the next decade or so, I am quite sure, this will transform, the economic and social scene, in our country beyond recognition. So, our challenge is to tackle problems of inflation without hurting the animal spirits of our entrepreneurs, without curbing the growth impulses and, that therefore, this gives the impression, some times, that the Government is hesistant in dealing with inflation. Some times, it gives the impression that we have taken action, but taken action with delay. Yesterday, I heard my esteemed friend, Shri Arjun Sengupta, say that there has been mismanagement. Without going into any of those things, I do wish to assure the House that the Government is very serious about bringing inflation under control. We are very conscious of the harmful effect that inflaton has on the living strategies of the poorer sections of our society, and that even in the past we have made every effort to protect this section. That effort will continue.

The last three years that our Government has been in office, we have not raised the prices of foodgrains from the Public Distribution System aplicable to people below the poverty line. Despite a sharp increase in petroleum prices from about 22-23 dollars to 60-75 dollars, we have not allowed the poor consumers of kerosene to suffer. We have tried to

protect to the extent possible those who use diesel in their operations and it will be our effort that in devising effective and anti-inflationary strategy, the needs of the poorer sections of our society will be kept fully in mind. And also, the best policy to deal with inflation, of course, is to address the question of the rate of inflation and I do believe that we will succeed in getting mastery over the inflationary impulses that have, I think, in recent months, somewhat got out of hand.

The House shoud appreciate that supply side shortages can be relieved through imports. But there is a particular difficulty in such a grave situation where not only petroleum prices are rising but also the prices of primary commodities like foodgrains, vegetable oils and other commodities are also rising. Our effort has been to bring in these imports without affecting the profitability of the domestic agriculture. It is true that looking back, if we had decided to import the five and a half million tonnes of wheat that we imported last year a littler earlier, it would have helped to moderate inflationary impulses. But we were torn between, I think, two conflicting considerations. There was one thing that we should n't do anything to curb the profitability of domestic agriculture and there was the other one, of course, trying to stabilise prices. In the process, some delay took place. But that I think is a thing of the past. The House should appreciate that when international prices of wheat, maize and vegetable oils have gone up, partly due to crop failures and crop shortfalls elsewhere and partly because of increased demand for use in production of bio-diesel, there are limitations to what extent we can use increased imports in reducing domestic inflationary pressure. And the House should know that in recent months, dealing with the problems of petroleum shortage, more and more countries are turning to bio-diesel. If more and more bio-mass is beign used to produce bio-diesel, that will put pressrue on prices of foodgrains, that will put pressure on prices of feedstock, that will in turn have effect on the world prices of poultry and the world prices of animal husbandry products. But that is a distant prospect. As of now, I am convinced that the monetary measures taken by the Reserve Bank will moderate growth of money supply. The measures announced by the Finance Minister to reduce customs duties on essential commodities and arrangments being made to augment domestic supplies through imports will have the desired stablising effect. In the medium term, of course, we must evolve a more effective strategy to increase production of foodgrains,

vegetable oils and pulses. Shri Jaswant Singhji asked me why I should write to Chief Ministers for controlling inflation. The answer is quite obvious. If we have to devise anti-inflationary strategies, States have a very important role to play. Agriculture is by and large in the State sector. If we want more foodgrains, if we want more production of pulses, if we want more production of oilseeds, we require the cooperation of States. Moreover, if the Public Distributon System is to be strengthened to protect the weak and vulnerable sections of our population, who else but the State Governments should I turn to? If dehoarding operations have to be launchd, who else should I turn to, but the State Governments? I think the Central and State Governments are active partners in managing the economy and it is this concern which led me to write to State Chief Ministers, inviting their attention, inviting their cooperation, in ensuring that we jointly succeed in controlling the inflationary impulses in the economy. I have set up, in the Cabinet Secretariat, under the Chairmanship of the Cabinet Secretary, a monitoring group which monitors the evolving price situation on a day to day basis and it is constantly in touch with various State Governments. Wherever shortages appear, effective action is being taken to deal with the shortage.

Sir, in the medium term, I have said the solution to problems of inflation lies in improving the productivity of our foodgrain economy, productivity of our oilseeds economy, the economy of the production of pulses in our country. I am asking the Planning Commission and the Ministry of Agriculture to work out region-wise, agro-climatic zone-wise plans and programmes to revitalise our agricultural economy, particularly laying emphasis on the foodgrains economy, the oilseeds economy and the pulses economy. A meeting of the National Development Council will be called to discuss precisely what States and the Centre could do jointly to revitalise our agricultural economy, so as to find durable solutions to this problem of agricultural stagnation.

Sir, I should also mention that in the 21st century, water is going to emerge as probably the most severe constraint on processes of development. Therefore, rational use of our water resources is of critical importance for sustaining the growth momentum of our economy. Therefore, the management of our water resources and putting in place viable and effective arrangements for the resolution of inter-State water disputes is critical for sustained development of agriculture and of industry in years

to come. I call upon all political parties to treat water as a national resource and work together in a spirit of national unity and harmony to resolve these difficult issues. Sir, I should say a few words about internal security as some hon. Members have referred to this issue. The hon. Leader of the Opposition, Shri Jaswant Singh, commented that the President's Address has not paid enough attention to this. Sir, he may have been satisfied with more words, but let me assure him and other hon. Members that in terms of real hard work on the ground our Government and our Home Minister have an enviable record to show much better than that of the previous Government. Be it the North-Eastern Region, be it Jammu and Kashmir or be in the naxalite-affected districts, the overall internal security situation is far better than what we saw during the previous regime. Even when we have had terorist incidents, like the ones we saw during the NDA rule, we have not had a breakdown of law and order and communal violence of the type we saw in the aftermath of Godhra in Gujarat. Compare the violence after Godhra incident in Gujarat to the situation in Maharashtra after the Mumbai blasts. Mr. Chairman, Sir, I agree that we could have waxed eloquent through the President's Address about all the work being done to minimise the loss to human lives after such terrible terrorist acts. That would have added several paragraphs to the speech! But let me take this opportunity to compliment our security and police forces for the exemplary manner in which they handled the situation, be it in Mumbai, be it in Malegaon, be it in Assam or be it in Nagpur, where a plan to attack the RSS headquarters was foiled. More importantly, our Government ensured that there was no communal violance as a consequence of such terrorist attacks. Rather, in Mumbai we saw the inspiring example of people coming out in thousands to stand up for peace and communal harmony.

Sir, we have been working in tandem with State Governments to tackle threats to national security, be they from terrorist elements, be they from naxalite elements. I myself have held a conference with Chief Ministers on this matter and committed Central support to any action by State Governments to improve their security situation. I think the hon. Leader of the Opposition himself asked the hon. Chief Minister of Chhattisgarh how much effort we have made to enable the State Government to cope with the problems of naxalite violence. As far as naxalism goes — and this is the most widespread internal security threat as seen in the recent shooting of a sitting Member of Parlimanet — we have consistently followed

a two-pronged approach to tackling this menace. On one front, we have been resolutely supporting States in improving the performance of their security and police forces taking up anti-naxal action. We are supporting them in cash and kind. We are supporting them through training, intelligence sharing. We are promoting greater coordination between States. At the same time, we are not ignoring the deep-rooted causes giving rise to disaffection among tribals and other sections in some parts of our country. The National Rural Employment Guarantee Act, the conferment of land rights on tribals in forest areas, the Backward Regions Grant Fund - all contribute to improving the economic lot of people living in naxal - affected regions. The aim is to ensure that they too benefit from the positive effects of the growth processes taking place in the rest of the country and avoid straying into the path of violence.

Mr. Chairman, Sir, Shri Jaswant Singhji stated that the President's Address had underplayed ULFA. I have always condemned violence and extremism in Assam and elsewhere and I have never hesitated to say that we can negotiate only with those who want peace, not with those who kill innocent people. We will never hesitate to sit down and talk to a fellow Indian if such conversation can bring peace to our people. But, we will never compromise the unity and integrity of our country or allow those who kill innocent people to go unpunished. It is with this in view that we began a dialogue with the People's Consultative Groups so that it may gradually extend to ULFA as well. As talks did not make headway, we continued with action by security forces. Mere mention of one insurgent group or the other will not serve any purpose. What is required is the will and resolve to maintain peace and order and defeat any terrorist designs. We shall fulfil this.

Sir, there has also been a mention by Shri Jaswant Singhji and Shrimati Sushma Swaraj that by repealing POTA, we have made an error and that this was nothing but abject surrender to tourists. Shri Jaswant Singhji used the phrase, 'terrorists should be terrorised'. While tough talking sounds good, what is important is the ground reality. I believe, Sir, it is important that while we fight terrorism with all the instruments at our command, we must not brutalise lives, our polity and our society. The extent of misuse of POTA is known to all and by repealing it, we have respected the sentiments of the ordinary people. Sir, in any case, I wonder how POTA had helped the previous Government prevent incidents at Akshardham,

Jammu or elsewhere. Effective policing and anti-terrorist action can be done even under existing laws. We are doing this and we will continue to do.

Sir, my esteemed friend, Shri Sitaram Yechury, and many hon. Members wanted greater attention to be paid to investing in the capabilities of our people. I should like to mention that the Finance Minister, in his Budget Speech, has already clarified that in addition to the outlays that are shown in the Budget paper, in the course of the year, he will find, at least Rs. 7000 crores of additional resources to be put into the development plan and this will go essentially to social development - education, health and rural development. Therefore, the feeling that we have not done enough for the social sector— I think if you take into account that particular statement- would, to that extent, get modified. Sir, it is our commitment we have made under the Common Minimum Programme that we will work to raise the allocation for education to 6 per cent, that we will work to raise the allocation for health to 2-3 per cent of our GDP. It cannot be done in a single year, but that is a commitment, by which we stand and I am confident that if the indian economy continues to grow at the rate of 8 to 9 or 10 per cent per annum, we will fulfil our commitment. Sir, this is our social commitment to the empowerment of the deprived sections through education through health, through vocationalisation of education. This is the way we believe we can empower our weaker sections to become partners in processes of economic growth and this is at the core of the new architecture of development that we are trying to put in place. The expansion of the Sarva Shiksha Abhiyan, the Mid Day Meal Programme, the ICDS, the National Rural Health Mission, the proposed National Vocational Education Mission, the Means-cum-Merit Scholarship at the secondary level announced in the Finance Minister's Budget-these are all initiatives which seek to invest in the capabilities of our people. Our goal of inclusive growth is focussed on creating conditions of rapid growth as well as growth of capabilities in our people to benefit from this growth. I am not going into a debate on the issue of allocation by sectors. However, the phenomenal growth in revenues—I compliment the Finance Minister for this - has enabled a quantum jump in investment in our priority flagship programmes. This year alone, they have an additional Rs. 33,000 crores. Education alocations have been more than tripled in three years from less than Rs. 10,000 crores to Rs. 33,000 crores. We are now going to rapidly expand secondary and higher education. The allocations for health,

education and rural development are at levels, both in absolute terms and relatively, which were unthinkable just three years ago. We are committed to doing more in these areas and we will do so.

My esteemed friend, Dr. Karan Singh, mentioned that we have not made any mention of family planning or population stabilisation in the President's Address. That does not mean that we do not recognise the importance of population stabilisation. Our sincere belief is that it is not through coercive policies but by educating our people, by investing in our people, by ensuring that all our children, particularly, the girl child, are in school and get quality education, that we will empower them to take charge of their own destinies and that is the best environment which will promote effective family planning through voluntary acceptance of the small family norm. So, the holistic approach to healthcare that we have through the National Rural Health Mission, I am sure, will make a material contribution to population stabilisation without involving any coercion in the process of implementation.

Sir, some hon. Members, particularly, Shri Sitaram Yechury and Shrimati Sushma Swaraj, have referred to the Special Economic Zone policy. I have already mentioned, Sir, India needs to industrialise in a big way, if we have to realise our manifest economic and social destiny. We are living in a world, whether we like or not, a globalised world, where both capital and skilled labour are today increasingly mobile, both nationally and internationally. Therefore, we have to put in place an incentive system, which would make India an attractive destination for investment and this is a philosophy which has led to the creation of this concept of Special Economic Zones. We are a large country. It is not possible to modernise our physical and social infrastructure all over the country in one go. The experience of China also suggests that even when you have ample resources, it is not possible to spread them too thinly, and, therefore, it was felt that maybe, in the short run to medium term, it is necessary to devise a new concept of Special Economic Zones, whose primary attraction will be the provision of modern infrastructure to attract investment.

In the process, certain other issues have arisen, Whether we have overdone with regard to tax incentives, about the settlement and rehabilitation of people whose lands are taken away. Those are legitimate concerns. I am myself sensitive to some of these concerns. My senior colleague, Shri Pranab Mukherjee is heading a Group of Ministers, which

is looking into this matter, and, I assure the House that whatever anomalies may have crept into this scheme, will be taken care of.

Sir, it goes without saying that increased spending is only one part of the equation of getting our country moving on the road to accelerated growth. We have simultaneously to ensure that the resources that are allocated are well spent. Therefore, the great importance of improving the quality of governance. And that is the point that my esteemed friend, Dr. Karan Singh, emphasised in his opening speech.

I share the concern which several hon. Members have expressed about the quality of governance. We need to have much better leakage-free implementation of programmes if we have to achieve the desired outcomes from the increased spending that we are undertaking goes without saying. The thousands of crores of rupees that are being funnelled into development programmes will not bear fruit unless they are spent wisely and ethically. State Governments and local bodies have a major role in ensuring this. The Right to Information Act goes to some extent in bringing in accountability into governance processes. At the same time, Sir, we need a change in mindsets if we have to root out corruption. Our Government will work with States in ensuring that development outcomes match our outlays.

Sir, Shri Sitaram Yechury referred to the problem of communalism and pointed out that the President's Address did not draw attention to this very important issue. Sir, I assure him that the resurgence of communalism and the growing signs of intolerance in some parts of our country do worry us. The UPA Government came to power because the people of our country rejected the forces of communalism and sectarianism. Our inclusive culture and our inclusive civilisational inheritance have no space for such intolerance.

Sir, we are an open society. Some ask whether we are becoming an open society with a closed mind. I certainly hope it will never happen. Sir, the UPA Government will never allow anyone to weaken our democratic traditions. At the same time, we will never allow any force to break the unity of our people. We remain committed to our constitutional and national values of secularism and pluralism.

I share the concern expressed by hon. Members about signs of communal resurgence and sectarian intolerance. We too receive such reports from some parts of our country. I assure all Members and every

citizen of our country that we will fight communalism and sectarianism in all their forms and manifestations. We will defend the secular and pluralistic basis of our democratic Republic.

Sir, I should say a few words about the Sachar Committee. Sir, hon. Members have referred to the need to ensure that minorities too benefit from our growth processes and to ensrue that they are not left behind. The Sachar Committee has brought out the stark reality about the conditions of the Muslim minority community in our country. The new 15-point Programme is therefore focussed on ensuring an equitable sharing of the benefits of crucial development programmes in health and education. We are also designing targeted programmes for minority concentration districts and we make no apology about it. In the long run, as all communities catch up in their social indicators, there would, of course, be no need for such programmes. But given the current disparities, it is imperative that we carry all sections along. All sections of our community should have the feeling that they are partners in processes of development.

Mr. Chairman, Sir, I should say a few words about Foreign Policy. Issues have been raised by several hon. Members. I feel satisfied that we have been able to forge a broad national consensus on our foreign policy orientation. As I have often said, our policy reflects our 'enlightened national interest.' We regard our national security and the need to create a global environment conducive to our rapid economic development as the key defining elements of our foreign policy. We also regard peace and stability in our region as a key objective of our foreign policy. The goal of our foreign policy is to expand the developmental options that are available to us, to expand the possibilities for our citizens to exhibit their inherent enterprise and creativity; and to facilitate the creation of a progressive, equitable and inclusive nation living in harmony with its immediate and wider neighbourhood. If our foreign policy initiatives are seen through this prism, it would be apparent that there is consistency in our approaches in every sphere.

In the last two years, our relations with Russia, the United States, the European Union, China, Japan and the ASEAN countries have all grown. We have expanded relations to cover many new areas and in all these regions, there is a growing realisation of the importance of India in world affairs. There is a realisation that the success of India as a nation has

deep implications and lessons for the world at large. Our success is a success of democracy, inclusiveness, harmony, openness and tolerance for diversity. It is this realisation that makes India a regular destination for all major world leaders. At the same time, our traditional relations with the Non-Aligned Movement, Africa and West Asia have also deepened and our Government proposes to expand these further in the coming years. The benefits of this extensive improvement in our relations has had tangible benefits for our people—in improving our trade, in increasing opportunities for employment, in expanding the reach of our businesses. I believe that we have crossed a significant point in our economic history where we are now seen as important partners in the evolving global economic and social order.

Sir, in our immediate neighourhood, we are looking forward to hosting the SAARC Summit early next month. India seeks a neighbourhood of peace, prosperity and mutually beneficial economic and social development in our vast sub-continent. I have often said that the destinies of the nations of South Asia are interlinked. We have not slackened in our efforts to promote peace and stability in this region. As the incoming Chairman of SAARC, we will expand the scope of our relations with all nations of the SAARC region. I am sure, Sir, the House will join me in expressing the hope that the SAARC Summit will be purposeful and productive and contribute to the progress and well-being of the people of South Asia as a whole.

Sir, we have been working purposefully for the allround improvement of our relations with Pakistan. This has borne fruit on certain fronts. We need to establish long-lasting peace, friendship and amity between our two countries. We will work resolutely in that direction. I am sure that through dialogue, we will be able to resolve all outstanding issues. And I have great hope in what the future holds for our two nations for our progress and for our prosperity.

Sir, some hon. Members have said, Shri Jaswant Singh was the one who said, that we have lost the strategic initiative in the dialogue with Pakistan and that we have no coherence in our approach. I wonder what 'coherence' means, coming as it does from someone whose Government mobilised and put the Army on the borders for almost a year with no results or gains whatsoever. We will not neglect the security dimension

under any circumstances. But, we will also not go down the beaten track of sabre-rattling to no purpose. We will work for long-lasting peace and stability in our region. I do agree that in the larger neighbourhood, there are many uncertainties and underlying tensions. Without wishing to pontificate, I can only say that these are all nations whose polity and society are rapidly changing and we all have to cope with the evolving situation to the best of our abilities keeping in mind our long-term goals. Sir, I should also like to say a few words about the Women's Reservation Bill. This is a matter which has figured in the debate; it figured in the debate in this House in the morning during Question Hour, and, Sir, I once again repeat that our Government is committed, and the Common Minimum Programme commits us, to work towards the reservation of seats for women in our State Legislatures and in our Parliament. I mentioned in the morning that I have been working very hard along with the Chairperson of the UPA, Shrimati Sonia Gandhi, to evolve a broad-based consensus. Some months ago, it appeared that we had succeeded, and therefore, in fact, I had announced that I look forward to bring in a Bill in the Parliament in the Session which has just come by, but that did not materialise. This does not imply any lack of interest. I will work for a broad-based consensus and ensure that we can secure such a consensus to bring this Bill to both Houses of Parliament as early as possible. This is the commitment which, as I said, figures in our Common Minimum Programme, and this is a commitment which I am committed to honour.

Sir, finally, in thanking the President for his Address to both the Houses of Parliament, I once again express my gratitude to all the hon. Members for their thoughtful comments on various issues of national, international and local concern. I respect the sentiments behind many of the cut motions tabled. Our Government will pay heed to each and every one of the valuable suggestion made and concerns expressed. With these words, Sir, I thank you.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the amendments for consideration. Amendment Nos. 49 to 55 by Shrimati Sushma Swaraj. Sushma Ji, are you pressing the amendments?

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदय, मेरे सात संशोधन हैं इस

राष्ट्रपति अभिभाषण पर। मैं उनको प्रेस तो कर रही हूं लेकिन मेरा जो एक संशोधन महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में है उसके बारे में दो मिनट कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने आज सुबह भी और आज अभी राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए भी उस प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वे विधेयक लेकर आएंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधान मंत्री जी, कल मैंने सदन में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था। आप उस समय सदन में नहीं थे। मैं केवल उस आंकड़े को दोहराना चाहती हूं ताकि आप और जितने मेरे अन्य साथी यहां बैठे हैं, जो कल उपस्थित नहीं थे, हम सब की आत्मा झकझोरेगी उस आंकड़े को देखकर। यह आंकड़ा मेरा नहीं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन आई॰पी॰यू॰ ने यह आंकड़ा प्रस्तुत किया है। दुनिया में कुल 189 देश हैं और महिला प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 108वें स्थान पर है और केवल इतना ही नहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 48वें स्थान पर है। तो हम दुनिया में तो 108वें हैं ही पड़ोसी पाकिस्तान से भी 60वें स्थान नीचे हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लज्जाजनक भी है। प्रधान मंत्री जी, मुझे केवल एक ही बात कहनी है। बहुत बार मैंने सोचकर देखा कि क्या यह स्थिति किसी और तरह से बदल सकती है। यह स्थिति किसी और तरह से नहीं बदल सकती सिवाए आरक्षण के। अगर हम यह सोच रहे हैं कि समाज की सोच बदलेगी, स्थिति रुटीन में बदल जाएगी तो 60 साल में बदली नहीं तो अगले साल में बदलेगी? तो मेरा केवल आपसे एक निवेदन है कि यह जो एक शब्द आप कमिटमेंट के बाद एंड में कहते हैं as early as possible, यानी जहां तक जल्दी होगी हम यह बिल लाएंगे, इसको थोड़ा बदल दीजिए। यह जहां तक जल्दी होगा as early as possible, हम पुराने 11 वर्ष से सुन रहे हैं। 1996 में यह बिल आया था, 2007 आ गया। मेरा केवल आपसे इतना निवेदन है कि आप इस प्रतिबद्धता को एक समयावधि में बांटकर यह कह दीजिए कि जो सलाह मशवरा आप कर रहे हैं उसको आप जल्दी से जल्दी समाप्त कर देंगे और इस बजट का जो दूसरा खण्ड होगा, मैं इस खण्ड की बात नहीं कर रही हूं क्योंकि वह अव्यवहारिक है, बीच में रिसेस होगा, जो बजट का दूसरा खण्ड होगा उसमें कम से कम बिल का प्रारूप आप ले आएंगे। चाहे पारित आप अगले सत्र में करायें, लेकिन कम से कम उस बिल का प्रारूप, एक ड्राफ्ट जरूर पेश कर दें, क्योंकि तीन साल से संसद के सामने कोई ड्राफ्ट नहीं है। पहले कम से कम एक ड्राफ्ट था, तो उम्मीद बंधती थी कि किसी दिन चर्चा के लिए आ जाएगा, अब ड्राफ्ट भी नहीं है। आप बजट के अगले खंड में, एक प्रारूप पेश कर देंगे, बस इतना भर कह दें, मेरा इतना ही आपसे निवेदन है।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, I respect the sentiments expressed just now by Sushmaji that the figure is very low in the lead

tables. When it comes to women's empowerment, it is a matter of deep regret and concern to me and to my Government.

As far as the reservation issue is concerned, I take note of the sentiments. I will make every honest effort to bring forward the Bill as early as I can. I think, beyond that, it would not be proper for me to say anything more!

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, शब्दों के पीछे उनकी भावना अच्छी है इसलिए मैं संशोधन प्रेस नहीं करूंगी।

Amendment Nos.49-55 were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Pyarelal Khandelwal is not here. I shall now put the Amendment Nos.56-63 moved by him to vote.

Amendment Nos. 56-63 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kalraj Mishra is not here. I shall now put the amendment nos.138-145 moved by him to vote.

Amendment Nos. 138-145 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment Nos.161-168 moved by Shri Shreegopal Vyas to vote. Are you withdrawing your amendments?

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): उपसभापति महोदय, मैं सम्माननीय प्रधान मंत्रीजी के विचारों को सुनने के बाद और जो आश्वासन उन्होंने सदन को दिए हैं और मुझे आशा है कि जो कुछ मेरे संशोधनों में कहा गया है, वह उन तक पहुंचाया गया होगा और वह सदन की भावनाओं को ख्याल में रखकर, आने वाले दिनों में, इसके संबंध में अपनी नीतियों के बारे में जरूर क्रियान्वयन करेंगे। इस आशा से और अपने नेता के द्वारा जो नीति अख्तियार की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए, मैं उनको प्रेस नहीं कर रहा हूं, किन्तु निवेदन कर रहा हूं कि इन बातों पर उचित ध्यान दिया जाए।

Amendment Nos. 161-168 were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That an Address be presented to the President in the following terms:—

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he

has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23, 2007."

The motion was adopted.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Bill, 2007

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharati) Bill, 2007, as passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 8th March, 2007.

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M.

The House then adjourned at four minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 9th March, 2007.

MGIPMRND—4008RS—4-2-2008.